● वर्ष-3
● अंक-43
रायपुर, गुरुवार
28 सितंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› बुढ़ापे से मुक्ति दिलाता है....

विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा

एक साथ चुनाव पर देने की कोई समय सीमा नहीं

नईदिल्ली। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतु राज अवस्थी ने बुधवार को कहा कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर काम अब भी जारी है और इस संबंध में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और ऑनलाइन प्राथमिकी सबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अवस्थी ने यहां संवाददाताओं से कहा, एक साथ चुनावों पर अब भी कुछ काम चल रहा है। हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं है। प्रक्रिया के अनुसार, विधि आयोग की सभी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। एक साथ चुनाव का मुद्दा वर्षों से विधि आयोग के पास लंबित है। पिछले विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए तीन विकल्प सुझाए थे, लेकिन कहा था कि कई बिंदुओं पर विचार किया जाना बाकी है। उसने अपनी मसौदा रिपोर्ट के साथ जारी एक सार्वजनिक अपील में कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में कई बाधाओं को दूर किया गया है लेकिन कुछ बिंदुओं पर अब भी विचार बाकी है। उसने सभी हितधारकों से यह सुझाव देने के लिए कहा था कि क्या एक साथ चुनाव कराने से किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान की मूल संरचना या देश की संघीय राजनीति के साथ छेड़छाड़ होगी। इसमें कहा गया था कि जब संसद या विधानसभा में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों ने सुझाव दिए हैं।

इन समितियों ने प्रस्ताव दिया है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति या चयन उसी तरीके से किया जा सकता है जिस तरह से सदन के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब मौजूदा विधि आयोग ने इस विषय पर आगे काम करना शुरू कर दिया है। पॉक्सो अधिनियम पर विधि आयोग की रिपोर्ट सहमति की उम्र के मुद्दे से संबंधित है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लें प्रधानमंत्री

कांग्रेस की मांग, सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान निकालें

नईदिल्ली। कांग्रेस ने मणिपुर में दो छात्रों के शवों की तस्वीर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद राज्य में पैदा हुए हालात को लेकर बुधवार को केंद्र और प्रदेश सरकार पर कानून-व्यवस्था की स्थिति संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लेना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की स्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकारें और सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रदेश में शांति बहाली का प्रयास करें। मणिपुर में दो युवकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर मंगलवार को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के कुछ घंटे बाद मणिपुर सरकार ने अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया।

इम्फाल घाटी में दो युवकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। इस हिंसा में

छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है।'' खरगे ने कहा, ''अब समय आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के भाजपा के अक्षम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उथल-पुथल की किसी भी संभावित घटना को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम होगा।''

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने संवाददाताओं से कहा, ''दुख की इस घड़ी में हम मणिपुर के छात्रों, शिक्षकों और मणिपुर के हर नागरिक के साथ खड़े हैं। मणिपुर का दर्द आज पूरा देश महसूस कर रहा है। मणिपुर में राज्य सरकार जिस तरह लाठियों और आंसू गैस के जरिये छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस उसकी निंदा करती है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को अपनी पीठ दिखा दी है। गोगोई ने सवाल किया, ''मणिपुर में करीब पांच महीने पहले हिंसा शुरू हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज तक वहां नहीं गए। क्या देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रचार और उद्घाटन के लिए बनाया है? हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते पांच महीनों में खुद कितनी बार मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से बात की है?''

उन्होंने यह भी पूछा, ''प्रधानमंत्री मोदी को और कितने सबूत चाहिए? वह मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश कब देंगे?'' कांग्रेस नेता ने दावा किया, ''मणिपुर में भाजपा की सरकार महिलाओं और बच्चों को बचाने में नाकाम रही है। वहां न जवान सुरक्षित हैं और न पुलिसकर्मी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद की छवि के मायाजाल में ऐसे फंस चुके हैं कि उन्हें देश की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं दे रही।'' गोगोई ने कहा, ''हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सारी पार्टियों की बैठक बुलाएं और हम सभी मिलकर मणिपुर की समस्या का कोई समाधान निकालें।

उत्तर प्रदेश की इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका

नईदिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। फूलपुर गांधी परिवार का गढ़ है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने यहां से 1952, 1957 और 1962 में लगातार तीन चुनाव जीते थे। यह यूपी में गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली तीन सीटों में से एक है, बाकी दो सीटें रायबरेली और अमेठी है। हालांकि, प्रियंका को किस संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा जाएगा, इस पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। सूत्रों का कहना है कि अगर पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो कांग्रेस मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रियंका को टिकट भी दे सकती है। इससे पहले, गांधी परिवार के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आई थीं, जहां प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो चुनावों से जीत रहे हैं। कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख अजय राय ने भी कहा कि उनके वाराणसी से चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर प्रियंका को लेकर सहमति बनती है तो कहीं ना कहीं फूलपुर या फिर जबलपुर से वह इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस बात का भी खुलासा नहीं किया गया है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं। हालांकि, प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा कई बार कह चुके हैं कि वह लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं।

विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए कोयलांचल क्षेत्र बिश्रामपुर में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन, स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा के मार्गदर्शन तथा अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की उपस्थिति में कॉर्मेल कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल बिश्रामपुर में आयोजित किया गया।

भारत में 40 फीसदी से ज्यादा बुजुर्ग गरीब: संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट

नईदिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की एक नयी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 फीसदी से ज्यादा बुजुर्ग संपत्ति के मामले में गरीब हैं और करीब 18.7 प्रतिशत बुजुर्गों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' में कहा गया है कि बुजुर्गों में गरीबी का यह स्तर उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर, भारत में हर पांच में दो बुजुर्ग संपत्ति के लिहाज से गरीब श्रेणी में हैं। यह जम्मू-कश्मीर में 4.2 प्रतिशत और पंजाब में पांच प्रतिशत है जबकि लक्षद्वीप में 40.2 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 47 प्रतिशत है।

उनके काम, पेंशन और आय की स्थिति के विश्लेषण से पता चलता है कि 18.7 प्रतिशत बुजुर्गों के पास आमदनी

का कोई जरिया नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 17 राज्यों में यह अनुपात राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। उसके मुताबिक, उत्तराखंड में यह 19.3 प्रतिशत है तो लक्षद्वीप में 42.4 फीसदी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वृद्ध महिलाओं में उच्च जीवन प्रत्याशा है, जो कई देशों की प्रवृत्ति के अनुरूप है। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, 60 साल की उम्र में, भारत में एक व्यक्ति 18.3 साल और जीने की उम्मीद कर सकता है, जो महिलाओं के मामले में 19 साल और पुरुषों के मामले में 17.5 साल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश और केरल में, 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्रमशः 23 और 22 वर्ष है, जो इन राज्यों में 60 वर्ष के पुरुषों की तुलना में चार वर्ष अधिक है जबकि राष्ट्रीय औसत में सिर्फ डेढ़ साल का अंतर है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 60 वर्ष की महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है, बुढ़ापे में गरीबी स्वाभाविक रूप से लैंगिक आधारित होती है जब वृद्ध महिलाओं के विधवा होने, अकेले रहने, आय का कोई स्रोत नहीं होने और अपनी संपत्ति कम होने तथा आश्रय के लिए पूरी तरह से परिवार पर निर्भर होने की संभावना ज्यादा होती है।

बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्ग विधवा महिलाएं अक्सर अकेली रहती हैं और उन्हें बहुत कम आश्रय मिलता है तथा उन्हें कई बीमारियां घेर लेती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्गों में महिलाओं का ज्यादा प्रतिशत जनसांख्यिकीय संरचना में उच्च असंतुलन को दर्शाता है। साल 1991 के बाद से, बुजुर्गों में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) लगातार बढ़ रहा है, जबकि सामान्य आबादी का लिंगानुपात स्थिर है। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2021 के बीच कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के तहत बुजुर्गों पर खर्च में 182 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

प्रमुख समाचार

नवीन पटनायक को बीजेपी ने दिया शून्य, कांग्रेस का भी निशाना

नईदिल्ली। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार को 10 में से रेटिंग दिए जाने की पृष्ठभूमि में, भाजपा और कांग्रेस की राज्य इकाइयों ने बुधवार को बीजद सरकार को भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे रहने के लिए शून्य रेटिंग दी। एक कार्यक्रम के दौरान, पटनायक ने प्रधान मंत्री की प्रशंसा की और उनकी सरकार को विदेश नीति और गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम के लिए 8/10 रेटिंग दी। भाजपा के विपक्ष के नेता जयनारायण मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए पीएम को 10 में से 10 अंक देना चाहिए। हालांकि, मैं पटनायक को उनकी सर्वांगीण विफलता के लिए शून्य देना चाहूंगा। पीएम का शासन भ्रष्टाचार है। पटनायक सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति ने कहा कि वह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को बड़ा शून्य देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी ओर, बीजद विधायक शशि भूषण बेहरा ने कहा कि पटनायक को मिश्रा और बाहिनीपति जैसे लोगों से रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। बेहरा ने कहा कि ओडिशा के लोगों ने लगातार पांच बार मुख्यमंत्री बनाकर पटनायक को पूरे अंक दिए हैं।

दूसरे राज्यों के चुनावों में जा रहे पंजाब के विमान: सिद्धू

नईदिल्ली। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को आरटीआई दायर किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इस्तेमाल किए गए निजी जेट विमानों पर खर्च का

हिसाब मांगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीएम की सहमति से प्रदेश के हर क्षेत्र में माफिया पनप रहा है। बुधवार को सिद्धू पंजाब के नागरिक उड्डयन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने जानकारी मांगी कि पंजाब सरकार ने पिछले डेढ़ साल में निजी जेट किराए पर लेने पर कितना खर्च किया है। पंजाब सरकार अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए निजी जेट किराए पर लेती है और पार्टी-विशिष्ट कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने कहा, यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की जनता के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में माफिया पनप रहा है और मान सरकार राजस्व पैदा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

नौसेना नया स्वदेशीकरण रोडमैप पेश करेगी

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना अगले सप्ताह एक अद्यतन स्वदेशीकरण रोडमैप का अनावरण करेगी और दो दिवसीय विशाल संगोष्ठी में पानी के भीतर

ड्रोन, अग्निशमन प्रणाली और रोबोटिक्स से संबंधित घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि पानी के अंदर काम करने वाले ड्रोन, हथियारबंद नौकाएं और अग्निशमन प्रणालियों सहित विभिन्न सैन्य हार्डवेयर में उपयोग की जाने वाली पचहत्तर प्रौद्योगिकियों को सेमिनार में प्रदर्शित किया जाएगा। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नौसेना ने पिछले साल स्वावलंबन सेमिनार में 75 प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का संकल्प लिया था और लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा, '' पिछले साल, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कम से कम 75 प्रौद्योगिकियां विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई थी। पिछले साल किए गए वादे पूरे किए गए हैं।'

केजरीवाल के बंगले पर खर्च की जांच करेगी सीबीआई

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण को लेकर लगे आरोपों की

सीबीआई जांच के आदेश दिए। जांच एजेंसी ने बाद में मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के अधीन लोक निर्माण विभाग को 3 अक्टूबर तक सभी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के बाद सामने आई कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच करेगी। जांच का आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा मई में सीबीआई निदेशक को लिखे गए पांच पत्रों के पत्र के आधार पर दिया गया है। इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एक विशेष ऑडिट का भी आदेश दिया गया है। इस साल की शुरुआत में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के सिविल लाइंस में अपने आधिकारिक आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया।

भारत विरोधी साजिशों का लॉन्चिंग पैड बन गया कनाडा

नईदिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने खालिस्तानी आतंकवादी समूह और अंडरवर्ल्ड के बीच संबंधों के जाल का पर्दाफाश किया है। जांच इस

बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे कनाडा और यूरोप के कुछ देश खालिस्तानी आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रजनन स्थल बन गए हैं। अदालती दस्तावेज़ इन परेशान करने वाले संबंधों की सीमा को दर्शाते हैं। एनआईए के निष्कर्षों के अनुसार, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहने वाले सिख समुदाय से धन प्राप्त करता है, जिसका उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में किया जाता है। बीकेआई को कनाडा के विभिन्न शहरों में सिख रैलियों और धन उगाहने वाले कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से आयोजित करने और उनमें भाग लेने के लिए जाना जाता है। विदेशों में एकत्र किया गया ये धन भारत को लक्षित करने वाली गतिविधियों में अपना रास्ता खोजता है। एनआईए के निष्कर्षों से भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधियों में से एक कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बीकेआई के संबंधों का भी पता चला।

दक्षिण में भाजपा के लिए मुश्किल, बदल सकते हैं सियासी दोस्त और दुश्मन

आर. राजगोपालन

अन्नाद्रमुक का एनडीए से बाहर निकलना और लोकसभा चुनाव के लिए नए मोर्चे के गठन की घोषणा करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक बड़ा झटका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में तीसरी बार वापसी की रणनीति बना रही है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम का असर तमिलनाडु की राजनीति पर पड़ सकता है और द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन की छोटी पार्टियां ज्यादा सीटें पाने के लिए अन्नाद्रमुक के साथ सौदेबाजी कर सकती हैं। इससे कांग्रेस भी प्रभावित हो सकती है। परिकल्पना कीजिए कि यदि यह सब होता है, तो इससे विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है, जिसके फलस्वरूप तमिलनाडु में द्रमुक-कांग्रेस के बीच गठजोड़ भी प्रभावित हो सकता है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अब करीब आठ महीने ही बचे हैं। ऐसे में अगर तमिलनाडु की राजनीति में उथल-पुथल और भ्रम की स्थिति बनी रही, तो जाहिर है कि इसका फायदा राज्य में सत्तारूढ़ दल यानी एमके स्टालिन की द्रमुक को मिलेगा। जयललिता के शासन काल में अन्नाद्रमुक भाजपा का एक भरोसेमंद और विश्वसनीय सहयोगी रहा है, जिसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया। जयललिता ने अन्नाद्रमुक के चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। अन्नाद्रमुक समान विचारधारा वाली ऐसी पांचवीं पार्टी है, जो एनडीए से बाहर हुई है। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल (यूनाइटेड) इत्यादि ने पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया और

नरेंद्र मोदी सरकार से खुद को अलग कर लिया था। निश्चित रूप से इसने एनडीए को प्रभावित किया। अन्नाद्रमुक द्वारा भाजपा से रिश्ता खत्म करने के बारे में कई कारण बताए जा रहे हैं। इस कहानी में अभी कई मोड़ आएंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि अगले एक महीने में तमिलनाडु की राजनीति में काफी बदलाव आएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया में भी एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। यदि कांग्रेस को 20 लोकसभा सीटों की पेशकश की जाती है और वह अन्नाद्रमुक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो द्रमुक के अध्यक्ष एमके स्टालिन क्या करेंगे?

नई दिल्ली में भाजपा नेताओं ने अन्नाद्रमुक पर आरोप लगाया कि वह सनातन धर्म वाले मुद्दे पर चुप रही। अमित शाह ने एडप्पादी पलानीस्वामी से स्पष्ट रूप से कहा था कि अन्नाद्रमुक द्वारा उदयनिधि स्टालिन की आलोचना करते हुए एक प्रेस बयान जारी किया जाए। लेकिन अन्नाद्रमुक द्वारा भाजपा और एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ने के पीछे कुछ और कारण बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, अन्नाद्रमुक चाहती थी कि भाजपा अपनी तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के अन्नामलाई को पद से हटा दे या उस पर अंकुश लगाए। लेकिन जब भाजपा ने इससे इन्कार कर दिया, तो अन्नाद्रमुक ने एनडीए से रिश्ता खत्म करने की घोषणा कर दी। बताया जाता है कि पिछले हफ्ते अन्नाद्रमुक के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और भाजपा नेता के अन्नामलाई को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी, क्योंकि पिछले दिनों अन्नामलाई ने द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुरई के खिलाफ एक आलोचनात्मक टिप्पणी की थी। लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसा नहीं करना चाहते थे। इस तरह से अन्नाद्रमुक सीट बंटवारे को लेकर नहीं, बल्कि राज्य भाजपा प्रमुख द्वारा अपने संस्थापकों के अपमान के कारण एनडीए गठबंधन से अलग हो गई।

गौरतलब है कि अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु में 'एन मन एन मक्कल' यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और राज्य में पार्टी के लिए एक मजबूत आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भाजपा नेतृत्व अन्नामलाई का समर्थन कर रहा है। यह यात्रा आगामी 11 जनवरी, 2024 को चेन्नई में खत्म होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी यात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किए जाने की उम्मीद है। भाजपा नेताओं को आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ न बोलने की सलाह दी गई है। लेकिन कम से कम दो भाजपा नेताओं ने बताया कि उम्मीद की किरण अब भी बची हुई है, क्योंकि भाजपा को अब तमिलनाडु में अपने पैर जमाने और 2024 के लोकसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का मौका मिला है।

फसलों को रौंद 41 हाथियों का दल हरमोर-आमाटिकरा पहुंचा

कोरबा। कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज के सेमरहा सर्किल में लगभग एक सप्ताह तक उत्पात मचाने के बाद 41 हाथियों का दल हरमोर.आमाटिकरा पहुंच गया है। हाथियों ने सेमरहा सर्किल के आधा दर्जन गांवों में लगभग 300 ग्रामीणों के फसल को रौंद दिया है। हाथियों के दीगर क्षेत्र में जाने पर वन विभाग का अमला नुकसानी का आंकलन तेज कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हाथियें के उत्पात में ग्रामीणों को कई लाख का नुकसान उठाना पड़ा है।

हालांकि वन विभाग पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा देने का प्रबंध करेगा। लेकिन वन विभाग द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा इतना कम होता है कि नुकसानी की तुलना में नहीं के समान। जिसके कारण ग्रामीणों को आर्थिक क्षति पहुंचती है। इस बीच पसान रेंज में मौजूद खतरनाक दंतैल पनगंवा पहुंच गया है। दंतैल का लोकेशन आज सुबह यहां के जंगल के कक्ष क्रमांक ओए.626 में मिलते ही वन विभाग का अमला तत्काल मौके पर

पहुंचा और ग्रामीणों को सतर्क करने के साथ ही लोनर की निगरानी में जुट गया है। वहीं कोरबा वनमंडल के पसरखेत रेंज में पिछले दो दिनों से सक्रिय 9 हाथियों का दल बीती रात मदनपुर जंगल होते हुए कोल्गा पहुंच गया। हाथियों ने यहां पहुंचने से पहले रास्ते में कई ग्रामीणों की फसल को तहस.नहस कर दिया है। हाथियों द्वारा फसल रौंदे जाने की सूचना पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर नुकसानी के आंकलन में जुट गया है। वहीं कुदमुरा रेंज में भी दो लोनर हाथियों की बीती रात अचानक एंट्री होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। एक लोनर हाथी धरमजयगढ़ क्षेत्र से पहुंचा है जबकि दूसरा छाल रेंज से। छाल रेंज से पहुंचे लोनर हाथी ने करतल रेंज के कल्गामार में फसल चौपट करने के बाद कुदमुरा के निकट जामनारा पहुंच गया और यहां के जंगल में विश्राम करने लगा। जबकि धरमजयगढ़ क्षेत्र से पहुंचे दंतैल ने गीतकुंआरी में उत्पात मचाते हुए ग्रामीणों की खरीफ फसल रौंदी है। दो लोनर हाथियों के क्षेत्र में पहुंचने पर वन विभग का अमला सतर्क हो गया है। लोनर की उपस्थिति वाले क्षेत्र में मुनादी कराने के साथ ही ग्रामीणों को सतर्क करने का काम शुरू कर दिया गया है।

कोरबा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना उतारेगी प्रत्याशी

कोरबा। कोरबा में 26 सितंबर दिन मंगलवार को छत्तीसगढ़िया क्रान्ति कोरबा चुनाव प्रभारी हिमांशु साहू, सूरज पटेल का आगमन हुआ है जिसमें घंटाघर सियान सदन में चुनाव प्रभारियों का स्वागत अभिनंदन कोरबा जिला के जिला और खड़ प्रभारियों द्वारा किया गया है, जिसमें चुनाव से संबंधित सभी बातों को किया गया और जिसमें जिला के सभी छत्तीसगढ़ियों को किस तरह एक जगह लाया जा सके जिसमें हमें छत्तीसगढ़िया लोगों के हितों में कैसे काम हो इस पर गहन मनन चिंतन कर किया गाया। चुनाव प्रभारी हिमाशु साहू दावरा बताया गया की जिला प्रथम चरण मे कटघोरा विधानसभा, पाली तनाखार विधान सभा में होगा सघन बैठक और चर्चा।

दूसरे चरण में कोरबा विधानसभा ओर रामपुर विधानसभा में लेगे बैठक। चुनाव प्रभारी ने कहा जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रत्याशी बनना चाहते है अपने आवेदन ओर बायोडाटा जमा कर सकते हैं । जिस पर अतिंम विचार प्रदेश कोर कमेटी को भेजा जायेगा। अतुल दास महंत जिलाध्यक्ष ने सभी खंड पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी को चुनाव प्रभारी के सहयोग के लिये दिशा निर्देश दिया। प्रदेश मंत्री दीलिप मिरी ने भी अपने विचार रखा जिसमे सभी पदाधिकारी व सेनानी को बताया की छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विगत 8 वर्षों से जो काम हमारे संगठन ने किया है। वो छत्तीसगढ़िया समाज के हित मे हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़िया समाज के हित मे काम होगा और पदाधिकारी ओर सेनानी ने अपन विचार रखा। सभी ने छतिगाढिया वादी विचार धारा के प्रत्याशी को विजय बनाने के लिये सकलप लिया। आज के बैठक में छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति सेना के पदाधिकारी विमला धुरव, जयंती प्रभा महंत, सुनिता, दीपका पदाधिकारी, दीदी, और सभी खंड के पदाधिकारी गमबीर दास, सुनील मानिकपुरी, ऐलेकस टोपो, विनोद सारथी, हेमत नामदेव हरि चोहान, संजू, गोसवामी राजेश शाहू, साहिल भारद्वाज, प्रताप सिह, राजेंद्र मिरी, लक्की सोनी, विशवेश देवागन, उमा गोपाल भरत पटेल, छोटेलाल, राहुल बंजारे, अजय केंवट और सेनानी पदाधिकारी शामिल हुए।

श्रवण मरकाम को बेलरगांव मंडल में मिल रहा भरपूर समर्थन

नगरी। भारतीय जनता पार्टी सिहावा विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी श्रवण मरकाम का मंडल बेलरगाव के ग्राम-साहनीखार,लटियारा, बोकराबेड़ा,दोहलापारा,नयापारा, गढ़डोंगरी, जरहीडीह, गिधावा, पावद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों व वरिष्ठ कार्यकर्ता से जनसंपर्क कर केंद्र में भाजपा की सरकार में जन्म से मृत्यु तक की योजनाओं को विस्तार से बताते हुए राज्य से भी कांग्रेस सरकार को हटाना है कहा। 'अउ नहीं सहिबो..बदल के रहिबो' .आगामी विधानसभा में भाजपा को जिताने व छत्तीसगढ़ में पुन: भाजपा की सरकार बनाने के लिए आग्रह किया। जिसमे मुख्य रूप से प्रत्याशी श्रवण मरकाम,मंडल अध्यक्ष अकबर कश्यप,महामंत्री मनोहर मानिकपुरी,शेखर अडील,मोहन पुजारी,दिव्येन्द्र परिहार,विनय देवांगन, मोनू साहू,सौरभ नाग, सहित ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बिश्रामपुर में हुआ शत-प्रतिशत मतदान जागरूकता कार्यक्रम

सूरजपुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए कोयलांचल क्षेत्र बिश्रामपुर में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन, स्वीप नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम,

संयुक्त कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा के मार्गदर्शन तथा अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की उपस्थिति में कॉर्मेल कान्वेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल बिश्रामपुर में आयोजित किया गया। जिसमें कॉर्मेल कॉन्वेन्ट स्कूल अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के छात्र-छात्राओं द्वारा रैली निकाला गया।

हाथों में मतदाता जागरूकता से संबंधित तख्ती, बैनर, पोस्टर लिए नारा लगाते हुए प्राथमिक शाला केशवनगर के प्रांगण से प्रारंभ कर केशवनगर सतपता चौक होते हुए कार्मेल कॉन्वेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के प्रांगण में एकत्रित हुए, जहां पर छात्र-छात्राओं द्वारा ई.व्ही.एम एवं व्ही.व्ही. पैट, स्वीप सूरजपुर आदि आकृतियां भी प्रदर्शित की गई तथा विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ने संबोधित करते हुए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार एवं शत-प्रतिशत मतदान का बहुत ही महत्व है। हम सबको मिलकर समस्त नगरवासियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। इस संबंध में सभी छात्रों को संकल्प दिलाया गया कि आप अपने आसपास के 10-10 मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करेंगे, साथ ही मतदाता जागरूकता हेतु शपथ भी दिलाया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी माध्यम की प्राचार्य सिस्टर मार्लिन, हिन्दी माध्यम की प्राचार्य सिस्टर जया ग्रेस, प्रभारी प्राचार्य सिस्टर थेरिस, खेल शिक्षक श्री एस.बी. शर्मा, स्कूल के समस्त शिक्षक छात्र-छात्राओं के अलावा जनशिक्षक गौरीशंकर पाण्डेय, पंकज सिंह, दयासिंधु मिश्रा, अनुरागवेन्द्र सिंह बघेल, मुन्ना प्रसाद सोनी, सुदर्शन दास, अजय देवांगन एवं बी.पी.ओ. साक्षरता जयराम प्रसाद का सराहनीय योगदान रहा।

एक महिला नक्सली के साथ तीन नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन नीति विश्वास, विकास एवं सुरक्षा की भावना एवं पूना नर्कोम अभियान-नई सुबह, नई शुरूआत के तहत नक्सली संगठन में सक्रिय1 महिला सहित 3 नक्सलियों कवासी चैतो (केएमएस सदस्या), माड़वी हांदा (आरपीसी कोषाध्यक्ष, मार्जुम पंचायत अन्तर्गत),माड़वी पोज्जा (प्लाटून मिलिशिया सदस्य) निवासी सभी तोंगपाल क्षेत्र के द्वारा बुधवार को नक्सल ऑपरेशन

कार्यालय सुकमा में तोमेश वर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी तोंगपाल एवं राजेश कुमार पाण्डेय सहायक कमाण्डेन्ट 227 वाहिनी सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है।

नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी तोंगपाल के नेतृत्व में क्यूआरटी तोंगपाल एवं 227 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा का विशेष प्रयास रहा। सभी आत्मसमर्पित नक्सली संगठन मे उपरोक्त पदों पर रहते हुये थाना तोंगपाल क्षेत्र में घटित विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल रहे है। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को राज्य शासन के पुनर्वास नीति के तहत् सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदाय किया जायेगा।

नक्सलियों ने 3 महिला नक्सलियों के मारे जाने से बड़ा नुकसान होना बताया

दंतेवाड़ा। नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने 20 सितम्बर को सुकमा-दंतेवाड़ा के सीमा क्षेत्र में नक्सलियों के डेरा पर मुखबिरी के सूचना पर सुरक्षाबलों द्वारा हमला करने की बात को स्वीकार करते हुए प्रेसनोट में बताया कि हमले में नक्सलियों के 3 महिला नक्सली मारे गए, मारे गए नक्सलियों को श्रद्धांजलि देने की बात कही गई है। मारे गए तीनों महिला नक्सली दरभा डिवीजन में सक्रिय थे। मुठभेड़ में मारे गए साथियों को दरभा डिवीजन के नक्सली संगठन ने बड़ा नुकसान होना बताया है। सुरक्षाबलों के इस हमले के रणनीति को सूरजकुंड योजना के तहत हमला करना बताया गया है।

गणेश विसर्जन के दौरान डीजे वाले बाबू को हिदायत तेज आवाज में बजाने पर जाना होगा जेल

दुर्ग भिलाई। दुर्ग पुलिस की ओर से त्यौहारों में डीजे बजाने वालों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। बुधवार को शहर एएसपी संजय कुमार ध्रुव ने पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों की बैठक की। बैठक में पुलिस की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसे लेकर डीजे संचालकों को चेतावनी भी जारी है।

गाइडलाइन का पालन न करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। गाइडलाइन के अनुसार किसी भी हालात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा करानी पड़ेगी। नई प्रक्रिया के तहत किस क्षेत्र से डीजे जाएगा? क्या समय होगा? ये जानकारी देना जरूरी किया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव ने कहा डीजे और धमाल की बुकिंग से पहले संचालकों को विधिवत प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर उसकी कॉपी संबंधित थाने में जमा कराए जाने का निर्देश डीजे संचालकों को दिया गया है। नियम का पालन न करने पर जुर्माना ठोका जाएगा। तेज डीजे बजाने वाले को जेल भी जाना पड़ सकता है।

साइलेंस जोन में डीजे बजाना प्रतिबंधित है। इन जगहों में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, न्यायालय, बुजुर्गों का निवास क्षेत्र और मजिस्ट्रेट की ओर से घोषित साइलेंस जोन सम्मिलित हैं। तेज आवाज में

डीजे बजाने पर डीजे संचालक को जेल भी जाना पड़ेगा। 60 डेसिबल से अधिक उंचे आवाज में डीजे या धुमाल बजाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत तीन साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने पर 15 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसमें पुलिस वाले वाहन का फोटो खींचकर रख लेंगे। बाद में ई चालान के तहत घर पर नोटिस भेजा जाएगा। डीजे संचालकों के किसी भी धर्म संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने बाले संगीत नहीं बजाने हैं। वरना उन पर कार्रवाई होगी।

बता दें कि बुधवार को एएसपी संजय कुमार ध्रुव ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की है। बैठक में पुलिस की ओर से डीजे संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन का पालन न करने पर डीजे संचालकों पर कार्रवाई का प्रावधान है। दरअसल, अक्सर देखा जाता है कि त्यौहारों में डीजे बजने से कई तरह के विवाद होते हैं। कई बार छोटा-मोटा विवाद बड़े अपराध का कारण बन जाता है। यही कारण है कि पहले से ही पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बारिश से लबालब घोघरा बांध में आई दरार, फूटने का खतरा

जशपुर। पत्थलगांव में चार दिनों से हो रही झमाझम बारिश से घोघरा बांध के एक हिस्से में बड़ी दरार आ गई है। बांध टूटने के खतरे को देखते हुए आसपास के क्षेत्र के किसान क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए श्रमदान कर रहे हैं। घोघरा सिंचाई बांध के फूटने के खतरे को देखते हुए तमता, चन्दागढ़, बटुराबहार के लोगों में दहशत बढ़ गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और किसानों का आरोप है कि घोघरा सिंचाई बांध की देख-रेख में जल संसाधन विभाग के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। चंदागढ़ के पूर्व सरपंच रोशन साय का कहना है कि घोघरा मुख्य बांध पर कई जगह दरार आ गई हैं। इससे बांध की मिट्टी लगातार धंस रही है। इन दिनों लगातार बारिश के बाद यह बांध लबालब भर जाने से मिट्टी का कटाव भी बढ़ गया है। स्थानीय किसानों ने घोघरा बांध का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होने के संबंध में पत्थलगांव विधायक और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। इसके बाद भी बांध की मरम्मत शुरू नहीं हो पाने से किसानों ने स्वत: श्रमदान का काम शुरू कर दिया है।

बैगा जनजाति के बच्चों को दी जा रही कंप्यूटर की शिक्षा

गौरेला पेंड्रा मरवाही। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासियों के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्रीय मद से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में विशेष संरक्षित जनजाति बैगा स्कूल आवासीय व्यवस्था के साथ शुरू किया गया है। तीन साल पहले शुरू हुए स्कूल में सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास रंग लाने लगा है। जिन बैगा आदिवासियों के माता-पिता शिक्षा से पूरी तरह अनजान थे, उनके बच्चे कंप्यूटर में इस तरह हाथ चला रहे हैं जैसे महानगर का कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल हो। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पहाड़ों में ऊंचाइयों पर रहने वाले बैगा आदिवासी समाज के बच्चों के विकास के लिए सरकार काफी योजनाएं चला रही है। हालांकि, उन योजनाओं का फायदा ज्यादा कम ही देखने को मिलता है पर केंद्रीय मद से संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विद्यालय में पिछले तीन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे पहली से तीसरी और पांचवी से आठवीं तक के बच्चों को विद्यालय में दी जा रही विशेष शिक्षा का असर देखने को मिल रहा है।

लैंडस्लाइड से ट्रेनों का दूसरे दिन भी संचालन प्रभावित

जगदलपुर। बस्तर से विशाखापट्टनम के बीच के रेल मार्ग पर भूस्खलन (स्ंदकेसपकम) होने की वजह से दूसरे दिन भी आवागमन बाधित रहा। दरअसल, ओडिशा में लगातार बारिश के चलते रविवार सुबह मनाबार और जड़ती स्टेशन के बीच पहाड़ से बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से रेल पटरी पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। घटना की वजह से इस रूट पर चलने वाली 8 यात्री ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। जिसमें चार ट्रेन बस्तर से जुड़ी हुई हैं। समलेश्वरी एक्सप्रेस, राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस, हीराखड एक्सप्रेस, नाइट एक्सप्रेस किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर भी दूसरे दिन बस्तर के लिए रद्द कर दी गई है। इस बीच यह ट्रेने कोरापुट स्टेशन से अपने गंतव्य तक चलाई जाएगी। इसके साथ ही मालगाड़ियों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटे के अंदर ही रेलवे को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। फिलहाल मौके पर रेलवे टीम लगातार मलबा हटाने के साथ मरम्मत का काम कर रही है।

ओडिशा से लाकर प्रतिबंधित तोता की बिक्री

गरियाबंद। वन विभाग ने प्रतिबंधित तोता की बिक्री करते दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से पिंजड़े में कैद 11 नग तोता जब्त किया है। वहीं मामले में वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए तस्करों को न्यायालय में पेश किया किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर ओडिशा के कालाहांडी से प्रतिबंधित तोता ट्रेन से लेकर में पहुंचे थे। नया रायपुर रेंज ने नवापारा सर्कल के डिप्टी रेंजर गिरीश रजक ने बताया कि आरोपी शंकर नायडूचुना भट्ठी रायपुर और लोकेश ढिढी धमतरी के निवासी है जो की आदतन तस्कर है। नयापारा शराब भट्ठी के पास पिंजरे में रखे तोता बेच रहे थे। सूचना मिलने पर 11 नग जब्त कर वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।दोनों आरोपी वन विभाग के कस्टीडी में है। पहले भी विभाग ने इन्हे रंगे हाथो पकड़ा था, लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया था। प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों के मुताबिक उन्हें ओडिशा के तस्कर रायपुर तक तोता लाकर देते हैं।

महापौर ने वार्ड क्र. 25 एवं 31 में किया जनसंपर्क दौरा

कोरबा। महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने निगम के कोसाबाड़ी जोनांतर्गत वार्ड क्र. 25 नेहरू नगर एवं वार्ड क्र. 31 दादर बस्ती का दौरा किया। उन्होने वहाँ के नागरिकों से भेंट की, उनकी समस्याओं की जानकारी ली एवं त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर श्री प्रसाद ने सड़क, नाली व साफ-सफाई जैसी मौलिक सुविधाओं से जुड़े कार्यो को प्राथमिकता के साथ संपादित कराने व इनसे संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। आज महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्र. 25 एवं वार्ड क्र. 31 दादर क्षेत्र का भ्रमण कर वहाँ के स्थानीय लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। दादर क्षेत्र के कंकालिन मंदिर के समीप आवासीय कालोनी के नागरिकबंधुओं ने अपनी समस्याओं के निराकरण कराऐ जाने का आग्रह किया, मुख्य मार्ग से कालोनी में प्रवेश करते ही कच्ची सड़क है, जिसमें चलने व गाड़ियों के आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर। विकासखंड बकावंड अंर्तगत ग्राम पंचायत तारापुर में सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर सैकड़ों ग्रामीण बुधवार को जगदलपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होने कलेक्टर विजय दयाराम को बताया कि सरपंच और अधिकारी गांव में कब्जों को खुला संरक्षण दे रहे हैं। ग्रामीणों ने अतिक्रमण पर कार्रवाई नही होने की स्थिति में उग्र कदम उठाने की चेतावनी दी है। कलेक्टर विजय दयाराम ने ग्रामीणों को जांच के बाद कार्यवाही करने के लिए आश्वस्त किया है।

बकावंड जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत तारापुर में बीते कुछ माह से अवैध कब्जों की बाढ़ आ गई है। कुछ स्थानीय रसूखदार ग्रामीण तथा अनेक बाहरी लोग गांव में स्थित सार्वजनिक प्रयोजन की चारागाह भूमि और सरकारी जमीन के साथ

ही वन विभाग की जमीन पर भी लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं। अवैध कब्जे की जमीन पर कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है, तो कोई खलिहान बना रहा है। अतिक्रमण की वजह से गांव में बच्चों और युवाओं के खेल मैदान, नए शासकीय भवन बनाने के लिए और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जमीन नहीं बची है। चराई जमीन भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है, जिससे गौवंश के चारे की समस्या पैदा हो गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और कुछ अधिकारी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। विरोध करने पर ग्रामीणों से दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे ग्रामीणों में भारी असंतोष पैदा हो गया है और गांव में कभी भी अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। इस गंभीर मसले को लेकर तारागांव के दो सौ से भी ज्यादा ग्रामीण 27 सितंबर को जगदलपुर पहुंचे थे। इन ग्रामीणों ने कलेक्टर बस्तर को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमणों के खिलाफ तथा सरपंच व संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ग्रामीणों में बुधसिंह भारती, फाल्गुनी पटेल, तुलाराम पटेल, भारत पटेल, मंगल राम कश्यप, बलि भारती, मैधर भारती, लखबंधु, धनुर्जय, सुकुलधर, समुंद्र, दुर्जन, महिला रायमती, सुखल, लीमबती, दयामती, सुखमती, कमल बती, गुरबारी सहित दो सौ से भी अधिक ग्रामीण शामिल थे।

जल जंगल जमीन के लिए राशन पानी और हथियार के साथ नारायणपुर पहुंचे अबूझमाड़ के आदिवासी

नारायणपुर। अपनी मांगों को लेकर 50 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर अबूझमाड़ के हजारों आदिवासी नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीण राशन पानी और पारंपरिक हथियारों के साथ साप्ताहिक बाजार स्थल बखरूपारा पहुंचे हैं। जहां वे धरना प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिले के अबूझमाड़ के माडोनार, ईरकभट्टी, तोयामेटा और ओरछा नदी पारा के हजारों आदिवासी पिछले 11 महीने से आंदोलन पर बैठे हैं। अब तक इनका आंदोलन जंगल में ही चल रहा था लेकिन अब वे बोरिया बिस्तर के साथ नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं। आदिवासियों को कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में आंदोलन के चलते शासन प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है इस वजह से अब वे मुख्यालय पहुंचे हैं। अबूझमाड़ के

हजारों ग्रामीण इससे पहले 7 जून और 13 मई को जिला मुख्यालय पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगों को जल्द से जल्द अमल में लाने की मांग की थी। अबूझमाड़ के आदिवासियों की तीन मांगे हैं। इन मांगों में नए पुलिस कैंप ना खोलने, पेसा कानून और वन संरक्षण अधिनियम 2022 में बदलाव शामिल है। जिसे लेकर वे सालभर से आंदोलन कर रहे हैं।

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय के साथ अबूझमाड़ तक पहुंची है विकास : मुख्यमंत्री

134.66 करोड़ की लागत वाली शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण कार्य का हुआ भूमिपूजन

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर शहर को 1021 करोड़ 59 लाख रूपए के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 7 बड़े विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने तात्यापारा नवीन मार्केट में स्थित छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा श्री खूबचंद बघेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए रायपुर शहर के लोगों को इन विकास कार्यों की सौगात दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने रायपुर शहर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है और सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ही इन विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन महीनों में ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 36 सौ करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है जिससे राज्य की जनता को लाभ मिलेगा। श्री बघेल ने कहा कि खारून नदी क रिवर फ्रंट निर्माण से शहर के लोगों को घूमने फिरने का एक नया स्थान मिलेगा जहां वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकेंगे। श्री बघेल ने कहा कि पांच वर्ष पहले खूबचंद बघेल एवं अन्य महान पुरखों के नक्शे कदम पर चलते हुए ही गढ़बो नया छत्तीसगढ़ का ध्येय रखा गया था और इसी के तहत सरकार लोगों की आय में वृद्धि और अधोसंरचना के लगातार निर्माण पर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम में उपस्थित लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने अपने संबोधन में एक हजार करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर रायपुर शहर के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पूरे प्रदेश में सड़कों एवं पुल पुलियों का जाल बिछाया गया है। श्री साहू ने कहा

कि सड़कों के निर्माण से लोगों की तकलीफें दूर होती हैं और जीवन सुगम बनता है।

तात्यापारा नवीन मार्केट में आयोजित इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री आलोक कटियार के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण उपस्थित थे।

इन कार्यों का हुआ भूमिपूजन

1. रायपुर शहर के नवीन मार्केट में आयोजित इस भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जी.ई. रोड के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के कार्य , जिसकी लंबाई 510 मीटर तथा निर्माण लागत राशि 134.66 करोड़ रूपए है, का भूमिपूजन किया । इस सड़क के चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा तथा शहर के लोगों को इस स्थान पर भारी ट्रेफिक से निजात मिलेगी।

2. रायपुर शहर के रिंग रोड क्र.1 एवं तेलीबांधा चौक से अग्रसेन धाम चौक लाभांडी तक 6-लेन फ्लाई ओव्हरब्रिज निर्माण कार्य का भूमिपूजन जिसकी निर्माण लागत राशि 473.13 करोड़ रूपए है।

3. रायपुर शहर में महादेवघाट एवं चंदनीडीह में खारुन रिवर फ्रंट के निर्माण, विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य जिसकी लंबाई 1.55 कि.मी. है एवं निर्माण लागत राशि 197.36 करोड़ रूपए का भूमिपूजन।

4. रायपुर शहर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग पर ऐलिवेटेड कॉरिडोर सहित एयरपोर्ट को जोडऩे वाले मार्ग का 6-लेन में निर्माण कार्य, निर्माण लागत राशि 156.27 करोड़ रूपए है का भूमिपूजन।

5. रिंग रोड क्र.1 पर उद्योग भवन महावीर नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर फ्लाई ओव्हर का निर्माण कार्य, लागत रु. 42.42 करोड़ रूपए का भूमिपूजन।

6.राजस्व एवं आपदा विभाग के अंतर्गत माडर्न तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य जिसकी लागत 11.50 करोड़ रूपए है का भूमिपूजन

7. छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के नवा रायपुर सेक्टर 24 कयाबांधा में निर्मित होने वाले प्रधान कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन।

मुख्यमंत्री ने लौटाई चिटफंड निवेशकों की राशि

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले कोरिया तथा बेमेतरा जिले के 122 पीड़ित निवेशकों को 38 लाख 40 हजार 684 रूपए की राशि लौटाई। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए।

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक कुल 69 हजार 503 निवेशकों को 38 करोड़ 08 लाख 67 हजार रूपए वापस लौटाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज बेमेतरा जिले के 108 निवेशकों को 34 लाख 63 हजार 684 रूपए तथा कोरिया जिले के 14 निवेशकों को 03 लाख 77 हजार रूपए ऑनलाईन खाते में अंतरित किए गए हैं। साथ ही अब तक 214 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध 468 प्रकरण दर्ज कर 587 डायरेक्टरों एवं 121 पदाधिकारियों कुल 708 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 402 प्रकरणों में चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार लगातार चिटफंड कंपनियों के निवेशकों की राशि लौटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां चिटफंड निवेशकों के पैसे लौटाए गए हैं। प्रदेश की भोली-भाली जनता को ठगकर चिटफंड कंपनियों ने उनसे अपने बचत राशि का निवेश कराया था। कंपनियां निवेश को दोगुना-तीनगुना करने का प्रलोभन देकर पैसे वसूलने का काम करती थी। श्री बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही चिटफंड निवेशकों का पैसा लौटाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। हमने लगातार कार्रवाई कर इस दिशा में सफलता हासिल की है और इसे आगे भी जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज जिन निवेशकों के पैसे लौटाए गए है, उन्हें बधाई दी। इस दौरान बेमेतरा जिले से जुड़ी हितग्राही श्रीमती सरस्वती साहू ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने सोचा नहीं था कि हमारा पैसा हमें वापस मिल पाएगा। लेकिन निवेशकों के लिए आपकी संवेदनशील पहल से मुझे अपने दो लाख 70 हजार रूपए वापस मिल पाए हैं। इसी तरह कोरिया जिले की चरचा निवासी श्रीमती उर्मिला को डेढ़ लाख रुपए और चिरमी निवासी श्री बालम साय ने उनके एक लाख रुपए वापस मिलने की खुशी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बात कर साझा की और उनके प्रति आभार जताया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव श्री चिंतामणि महाराज, विधायक श्री चक्रधर सिंह, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अंकित आनंद, श्री एस. भारतीदासन, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री महादेव कावरे उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

बसंत ने किया परिवर्तन यात्रा का स्वागत

रायपुर। भाजपा कार्यकर्ता एवं समाजसेवी बसंत अग्रवाल ने कल देर शाम राजधानी रायपुर के गुढियारी स्थित दही हाण्डी मैदान पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान अग्रवाल ने परितर्वन रथ में सवार होकर को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत के अलावा अन्य विशिष्टजनो को पुष्प गुच्छ भेट कर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर हजारों समर्थकों ने नारा लगाय कि बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। इससे पहले बसंत अग्रवाल ने दही हाण्डी मैदान में उपस्थित हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। परिवर्तन यात्रा में वरिष्ठ नेताओं के अलावा अजय जम्वाल, नितिन नबीन, पवन कुमार साई भी रथ में सवार थे।

राज्य सरकार ने ईडी के खिलाफ दायर दो में एक याचिका को लिया वापस

रायपुर। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ दायर दो में से एक याचिका को वापस ले लिया है जिसमें राज्य सरकार ने ईडी के खिलाफ कर्नाटक में दर्ज मामले के आधार पर छत्तीसगढ़ में हुई कार्रवाई को लेकर धारा 32 के की गई कार्रवाई के मामले को वापस ले लिया है। अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने बताया कि एक कर्नाटक में दर्ज मामले के आधार पर यहां हुई कार्रवाई को लेकर धारा 32 थी। वहीं दूसरी 141 के तहत पीएमएलए के प्रावधानों के खिलाफ दायर की गई थी। इसमें से राज्य सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि दूसरी याचिका को परस्यू करेंगे और धारा 32 की याचिका वापस लेते हैं। अपनी रिट याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार ने तर्क दिया था कि पीएमएलए का इस्तेमाल गैर-भाजपा राज्य सरकार के सामान्य कामकाज को डराने, और परेशान करने के लिए किया गया था। ईडी की कार्रवाई के बाद दो आईएएस, तीन राज्य सेवा अफसर और कई कारोबारी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ को उक्त याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस. वी. एन. की खंडपीठ ने राज्य को अनुमति दे दी।

ईद-मिलाद-उन-नबी पर विधानसभा अध्यक्ष ने दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को ईद-मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि-आज ही के दिन पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। जिन्होंने ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाकर समानता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि-हम इंसानियत की भावना को विकसित करके संसार को भाई-चारे का संदेश दे सकते हैं। इस अवसर पर डॉ. महंत ने मुस्लिम समाज का आह्वान किया कि-वे प्रदेश में सौहार्द्र एवं सद्भावना के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दें।

मुख्यमंत्री बघेल से आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में सौंरा, गोंड़, बिझिया, उरांव, भुंजिया आदि 12 समाज के प्रतिनिधियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल द्वारा विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर अंतर्गत डभरा में आगामी 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाले समाज के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का आमंत्रण दिया गया।

राजेश मूणत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनौती मंजूर

मुख्यमंत्री के 36 हज़ार करोड़ के विकास की खोज में दूरबीन लेकर खोजबीन करेगी भाजपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पीडल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जनता के बीच भ्रम फ़ैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने रायपुर शहर में सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रमों, अप्रत्यषित घोषणाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेश बघेल कितना भी भ्रम फ़ैलाने का प्रयास कर लें, हकीकत सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल जानते हैं कि वह झूठे हैं, वह भयभीत हैं,इसलिए शायद ही उनका न्योता स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। लेकिन भाजपा उनके कथन को सप्रमाण नकारेगी। मूणत ने बताया कि वह स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दूरबीन लेकर भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए कार्यों को खोजने निकलेंगे।

उन्होंने कहा कि आज से लेकर पिछले पौने 5 साल में भूपेश बघेल ने रायपुर राजधानी में एक भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट का भूमिपूजन नहीं किया जिसका लोकार्पण स्वयं तय समय में किया हो ,वह अब तक के भाजपा के पिछले कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुए कार्यों पर वाहवाही लूटने का प्रयास ही करते पाए जा रहे हैं। मूणत ने कहा कि

मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से इस कदर घिर चुके हैं कि कभी भी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई संभावित है। वह अच्छे से जान चुके हैं कि जनता ने मन बना लिया है और अब कुछ महीनों में कांग्रेस सत्ता से बेदखल होनी वाली है और वह चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए बचे खुचे दिनों में चुनावी घोषणा करके शिलालेख पर अपना नाम लगवाना चाहते हैं।

मूणत ने कहा कि आज जिस तेलीबांधा फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण का भूमिपूजन किया गया है, उसके निर्माणकार्य के लिए बजट की मंजूरी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में साल 2017 में ही दे दी गई थी, लेकिन भूपेश बघेल सरकार के काम की गति ऐसी थी की उनकी सरकार ने शायद कमीशन खोरी के चक्कर में जानबूझकर 5 साल तक उसका निर्माण रोककर रखा। 5 साल बाद एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर का लाभ नजर आ रहा है, जबकि पूर्व में बने एक्सप्रेस वे को जानबूझकर बाधित कर रखा गया था। बघेल ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक्सप्रेस वे को जांच के दायरे में डालकर जनता को उसका लाभ लेने से वंचित कर दिया। 5 साल होने के उपरांत आज तक जांच में कुछ नहीं निकला। खारून रिवर फ्रंट निर्माण का श्रेय लेने के लिए अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आवास एवं पर्यावरण मंत्री के तौर पर मैंने इसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, तब यही कांग्रेस इसका विरोध करती दिखती थी। राजेश मूणत ने शारदा चौक से तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण कार्य के भूमिपूजन को दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि तात्यापारा चौक सड़क के चौड़ीकरण को लेकर भाजपा के शासनकाल में सर्वे करवाया गया था, अगर वाकई में कार्य को अमलीजामा पहनाने मंशा होती, तो 5 साल बाद चुनाव तक इंतज़ार ना किया जाता। यह भूमिपूजन भी भूपेश बघेल की दूसरी घोषणाओं की तरह दिखावा ही साबित होगा।

मूणत ने कहा कि जिस रायपुर शहर को भाजपा सरकार के कार्यकाल में संवारा गया था, उसे कांग्रेस ने खोदापुर बना दिया है। भूपेश बघेल जानते हैं, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर बह है। रायपुर शहर की जनता भाजपा के साथ है, इसलिए चुनावी स्टंट के लिए घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर की चारो विधानसभाओं में भाजपा की जीत होगी। श्री राजेश मूणत ने कहा कि भाजपा सरकार के 15 सालों से अपने 3 महीने के कार्यकाल की तुलना करना हास्यास्पद हैं।

रायपुर में मनोज तिवारी का भूपेश बघेल पर तीखा हमला

रायपुर। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने भाजपा सांसद मनोज तिवारी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। तिवारी बिलासपुर के तखतपुर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा 2 में शामिल होंगे। रायपुर पहुंचने के बाद भाजपा सांसद ने भूपेश बघेल पर कई आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि छत्तीसगढ़ को उसका हक भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है।

मनोज तिवारी ने कहा छत्तीसगढ़ में जहां जहां से परिवर्तन यात्रा गुजर रही है वहां से बदवाल की बयार बहने लगी है। तिवारी ने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए है। पूरा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आए।

मध्य प्रदेश में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने पर भूपेश बघेल के हमले पर तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सांसद अगर विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं यानी भाजपा चुनाव को गंभीरता से ले रही है। जबकि कांग्रेस चुनाव के लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ये उनकी स्ट्रेटजी

है। गठबंधन सरकार पर भी मनोज तिवारी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार सनातन धर्म को खत्म करने की बात कह रही है। लेकिन ये अगर अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो किसी भी राज्य में कांग्रेस नहीं रह पाएगी। मनोज तिवारी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 75 प्लस के दावे पर भी हमला बोला। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस किसी तरह राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इज्जत बचाए हुए थी लेकिन भूपेश बघेल के कर्मों के कारण यहां से भी उन्हें हार मिलेगी।

प्रदेश सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश : साव

मुंगेली। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के गृह विधानसभा क्षेत्र मुंगेली पहुंची। जहां अरुण साव ने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों मे भारी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं प्रदेश की बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने राज्य को नशे का गढ़, धर्मांतरण का गढ़ बना कर रख दिया है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की बयार नजर आ रही है, युवाओं में सरकार के प्रति बेहद आक्रोश है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस सरकार को अरुण साव ने भूपेश-अकबर- ढेबर की सरकार बताया। अरुण साव ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से घबराकर कांग्रेस भरोसा यात्रा निकालने जा रही है।

छत्तीसगढिया ओलंपिक के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढिया ओलंपिक के समापन समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहुंचे। 25 सितंबर से शुरू हुए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छत्तीसगढिया ओलंपिक में 5 संभागों से आए 1906 खिलाडियों ने भाग लिया। जिसमें रायपुर संभाग के 383 खिलाडियों में से 18 वर्ष तक के 122, 18 से 40 वर्ष तक के 133 एवं 40 वर्ष से अधिक के 128 खिलाड़ी शामिल हुए। इसी तरह बिलासपुर संभाग के 384 खिलाडियों में से 18 वर्ष तक के 128, 18 से 40 वर्ष तक के 128 एवं 40 वर्ष से अधिक के 128 खिलाड़ी, दुर्ग संभाग के 379 खिलाडियों में से 18 वर्ष तक के 125, 18 से 40 वर्ष तक के 128 एवं 40 वर्ष से अधिक के 126 खिलाड़ी ने भाग लिया। सरगुजा संभाग के 380 खिलाडियों में से 18 वर्ष तक के 127, 18 से 40 वर्ष तक के 127 एवं 40 वर्ष से अधिक के 126 खिलाड़ी और बस्तर संभाग के 380 खिलाडियों में से 18 वर्ष तक के 127, 18 से 40 वर्ष तक के 128 एवं 40 से अधिक वर्ष से अधिक के 125 खिलाड़ी 16 खेल विधा में शामिल होकर अपना दमखम दिखाया। राज्य स्तरीय छत्तीसढिया ओलंपिक प्रतियोगिता रायपुर के 4 खेल मैदानों में हुआ। सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा में फुगड़ी, बिल्लस, भंवरा, बांटी (कांचा), रस्सीकूद एवं कबड्डी का आयोजन हुआ।

अधोसंरचना निर्माण से मिलेगी आर्थिक विकास को गति : बघेल

■ **वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेशवासियों को दी 4471 करोड़ की लागत के 2715 विकास कार्यों की सौगात**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर से प्रदेशवासियों को 16 विभागों के 4 हजार 471 करोड़ रूपए की लागत के 2715 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण-भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी विकास कार्य अधोसंरचनाओं के विकास से जुड़े हैं जो जनसुविधाओं को और बेहतर बनाएंगे। इन कार्यों का सीधा संबंध हमारे आर्थिक विकास से भी है। इन विकास कार्यों में 2 हजार 368 करोड़ रूपए की लागत के 1121 कार्यों का भूमिपूजन तथा 1705 करोड़ की लागत के 1530 कार्यों का लोकार्पण तथा 398 करोड़ रूपए लागत के 64 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने इस मौके पर राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में 60 करोड़ 40 लाख के लागत से बने सर्व सुविधा युक्त नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ भी किया और उन्होंने प्रदेशवासियों को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 05 सालों में सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ

अधोसंरचना निर्माण को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। हमारी जनहितैषी योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को समान रूप से मिल रहा है। लोगों की जरूरतों के अनुरूप हमारी योजनाएं बनी और उसके प्रभावी क्रियान्वयन ने छत्तीसगढ़ के विकास को गति दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नई दिल्ली में ठहरने के लिए छत्तीसगढ निवास के रूप में नया भवन मिल गया है। इससे प्रदेश के जरूरतमंदों को सहित सभी के रूकने-ठहरने की दिक्कत दूर हो जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दो दिनों के भीतर ही राज्य तथा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों तथा जनसुविधाओं से जुड़े 10 हजार 551 करोड़ रूपए की लागत के निर्माण कार्यों की सौगात प्रदेशवासियों को दी है।

उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिहदेव कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। श्री सिंहदेव ने अपने वर्चुअल सम्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का काम इसी तरह होता रहेगा। इन विकास कार्यों से आमजनों की सुवधिाएं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, श्री अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गृह श्री मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अंकित आनंद, श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, श्री एस. भारतीदासन सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर वर्चुअली शामिल हुए।

देश की राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में 60 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास में कुल 61 कमरे और 13 सूट हैं। यह भवन आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है। शासकीय अथवा निजी कार्य से दिल्ली जाने वाले छत्तीसगढ़वासियों की सुविधा के लिए यह भवन तैयार किया गया है। साथ ही चिकित्सा कारणों से दिल्ली जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी इस भवन में रूकने-ठहरने की सुविधा होगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के दो भवन पहले से ही दिल्ली में हैं, लेकिन बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए तीसरे भवन की भी जरूरत महसूस की जा रही थी। यह नया भवन चार मंजिला है। जिसमें सभी डाईनिंग, वेटिंग, कॉन्फेंस हॉल, गेस्ट रूम, डोर मेट्री, आवासीय लिफ्ट के साथ पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भूमिपूजन, लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 1284.42 करोड़ रूपए की लागत के 19 कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 404.02 करोड़ रूपए की लागत के 1192 कार्य, उच्च शिक्षा विभाग में 126.22 करोड़ रूपए लागत के 31 कार्य, गृह विभाग में 101.81 करोड़ रूपए लागत के 30 कार्य, क्रेडा विभाग में 49.88 करोड़ रूपए की लागत के 03 कार्य, आवास एवं पर्यावरण विभाग में 533.32 करोड़ रूपए की लागत के 17 कार्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 362.81 करोड़ रूपए की लागत के 09 कार्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 99.91 करोड़ रूपए की लागत के 04 कार्य, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 816.62 करोड़ रूपए की लागत के 146 कार्य, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 13.85 करोड़ रूपए की लागत के 06 कार्य, परिवहन विभाग में 72.34 करोड़ रूपए की लागत के 03 कार्य, अनुसूचित जनजाति विभाग में 133.76 करोड़ रूपए की लागत के 10 कार्य, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन में 146.53 करोड़ रूपए की लागत के 11 कार्य, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर एंड टेक्नालजी में 172.06 करोड़ रूपए की लागत के 331 कार्य, लोकनिर्माण विभाग में 144.5 करोड़ रूपए की लागत के 02 कार्य तथा अपेक्स बैंक में 9.8 करोड़ रूपए की लागत का 01 निर्माण कार्य शामिल हैं।

मझधार में फंस गए नीतीश कुमार

एक तरफ तो नीतीश कुमार के करीबी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा है कि इंडी एलायंस में नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला हो गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर बिहार में फिर से अटकलों का बाज़ार गर्म है कि वह एनडीए में जाने का रास्ता खोज रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर उनका लालू यादव के साथ समझौता नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वह जी-20 के मौके पर राष्ट्रपति के रात्रिभोज में शामिल हुए थे, और प्रधानमंत्री से मुलाक़ात भी की थी। अभी दो दिन पहले उनकी लालू यादव से मुलाक़ात हुई है। इस मुलाक़ात में लोकसभा सीटों के बारे में कोई चर्चा हुई या नहीं, यह नहीं पता लेकिन उससे पहले से यह चर्चा चल रही थी कि लालू यादव ने जेडीयू को आठ सीटें देने की पेशकश की है। फिलहाल जेडीयू के सोलह लोकसभा सदस्य हैं। 2014 में भाजपा को धोखा देने के बावजूद जब नीतीश कुमार 2017 में एनडीए में लौटे थे, तो भाजपा ने उन्हें समझौते में 17 सीटें लड़ने को दी थी, जिनमें वह 16 जीत गए थे। इसलिए उन जीती हुई 16 सीटों में से केवल आधी सीटों पर चुनाव लड़ने की लालू यादव की पेशकश नीतीश कुमार स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए दिल्ली में हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में नीतीश कुमार ने फारूख अब्दुल्ला से यह फार्मूला पेश करवाया था कि हारी हुई सीटों पर बातचीत हो, जीती हुई सीटें उसी दल के पास रहें जिसने 2019 में जीती थीं। लेकिन लालू यादव ने यह फार्मूला ठुकरा दिया था। अब नीतीश कुमार की लालू यादव से मुलाक़ात के बाद यह अटकल दुबारा से शुरू हुई है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जाने का रास्ता खोज रहे हैं। राजनीति में कई बार दबाव बनाने के लिए भी अटकलों का इस्तेमाल होता है। यह अटकल लालू यादव पर दबाव बनाने के लिए खुद नीतीश कुमार कैंप से फैलाई हुई हो सकती है। लालू यादव के बेटे और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन केन्द्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यह कह कर इन अटकलों को हवा दे दी कि अगर नीतीश कुमार वापस लौटते हैं, तो उनका स्वागत होगा। हालांकि नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लेने का फैसला करना उनके हाथ में नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को एनडीए में वापस लिया गया तो भाजपा में बगावत हो जाएगी। सुशील मोदी उन लोगों में से एक हैं, जो नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाने की बात कह रहे हैं। हालांकि भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह भी यह बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के वापस लौटने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर सुशील कुमार मोदी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर नीतीश को एनडीए में वापस लिया जाता है, तो भाजपा में बगावत हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उन्हें भी कहीं से यह भनक लगी है कि नीतीश कुमार कुछ कोशिश कर रहे हैं, और इंडी एलायंस बनने के बाद 2024 के गंभीर संकट को देखते हुए मोदी-शाह की जोड़ी पिघल सकती है। तो सुशील कुमार मोदी का यह बयान भी मोदी-शाह पर दबाव बनाने के लिए है कि वे ऐसी गलती न करें। सच यह है कि साल भर पहले नीतीश कुमार में जितना उत्साह था, इंडी एलायंस बनते ही वह ठंडा पड चुका है। साल भर पहले तो उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से लोकसभा चुनाव लड़ने का एलान भी करवा दिया था। यह भी एलान करवा दिया था कि वह बिहार से नहीं, उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश से इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी भी इसीलिए 2014 में गुजरात के साथ साथ यूपी से चुनाव लड़े थे। ललन सिंह ने यह भी बता दिया था कि वह उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए छोड़ने और लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने फूलपुर का दौरा भी किया था। उस समय नीतीश बड़े सपने देख रहे थे। वह हवा उड़ा रहे थे कि वह उत्तर प्रदेश की फूलपुर, मिर्जापुर या अंबेडकर नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इन तीनों सीटों पर उनकी कुर्मी जाति के वोट मायने रखते हैं। वह बिहार, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुर्मियों को भी अपने पक्ष में इकट्ठा करने की रणनीति बना रहे थे। वह बहुत बड़े सपने ले रहे थे कि विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन कर वह देश भर की कृषक जातियों कुर्मियों, पटेलों और जाटों को अपने पीछे लामबंद करेंगे।

भाजपा सांसदों को विधायक का टिकट

सिद्धार्थ शंकर गौतम

राजनीतिक शह-मात, गुटबाजी, कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने के बीच भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को लेकर असमंजस में थे किन्तु जैसे ही केंद्रीय कार्यालय ने भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की, कार्यकर्ता मानो सोती नींद से जाग गए। राजनीतिक पंडितों ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 7 हेवीवेट सांसदों, जिसमें तीन केंद्रीय मंत्री हैं, सहित राष्ट्रीय महासचिव को विधानसभा चुनाव का टिकट देकर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा देगा। यह दीगर तथ्य है कि जबसे गृहमंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ली है, वहां बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहे हैं। पहले जो 49 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी उसमें अधिकांश वे विधानसभा सीटें थीं जहां भाजपा लंबे समय से हार रही थी। ऐसे में ढ़ाई-तीन माह पूर्व प्रत्याशी चयन से भाजपा प्रत्याशी को क्षेत्र में संपर्क करने का पर्याप्त समय मिलेगा जिसका परिमाण सुखद भी हो सकता है। इसके पश्चात जारी 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची ने निश्चित रूप से कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी बढ़त बना ली है और अब कांग्रेस के समक्ष प्रत्याशी चयन की दुविधा मुंह बाये खड़ी है। दरअसल, दूसरी सूची जो जारी हुई है उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले की निवास सीट से, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से, सतना से सांसद गणेश सिंह सतना से, सीधी से सांसद रीति पाठक सीधी से, होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा से और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा क्रमांक एक से चुनाव लड़ते नजर आएंगे।

भाजपा नेतृत्व को आशा है कि कद्दावर नेताओं को टिकट देने से न केवल वो अपनी सीट जीतेंगे बल्कि उनके आसपास की सीटों पर भी इसका असर होगा और भाजपा की कमजोर दशा में सुधार होगा। विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद स्वाभाविक है ये नेता अब प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होंगे जबकि लंबे समय से प्रदेश की राजनीति से दूर थे। फग्गन सिंह कुलस्ते आखिरी बार 1990 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और 1992 तक विधायक रहने के बाद से 6 बार लोकसभा सांसद और एक बार राज्य सभा सांसद रह चुके हैं। यानि फग्गन सिंह कुलस्ते 33 वर्षों बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर 10 वर्षों बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वहीं प्रह्लाद सिंह पटेल का यह पहला ही विधानसभा चुनाव होगा। 6 बार के विधायक कैलाश विजयवर्गीय 2018 से प्रदेश की राजनीति से दूर हैं जबकि रीति पाठक पहली बार विधायक बनने के लिए मैदान में उतारी गई हैं।

गणेश सिंह अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे और उसके बाद से 4 बार सांसद रहे किन्तु अब एक बार पुन: वे केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगे। उदय प्रताप सिंह 2007 में कांग्रेस विधायक के रूप में विधानसभा में बैठे थे किन्तु इस बार वे भाजपा के टिकट पर वोट मांगते नजर आएंगे। इन सभी नेताओं में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी उछाला जाता रहा है किन्तु इस सूची के आने से इतना तो तय है कि यदि भाजपा अपनी सरकार बना लेती है तो इतने वरिष्ठ नेताओं में मुख्यमंत्री पद के लिए आपसी सहमति बनाना कठिन होने वाला है। बहरहाल, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरी सूची में बड़े केंद्रीय नेताओं को प्रदेश के चुनावी रण में उतारकर स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मध्य प्रदेश चुनाव को वह हलके में नहीं ले रहा है। वैसे भी केंद्र की राजनीति में विकल्प की कमी और चेहरे के अभाव ने नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने में नाकामी हासिल की है और संभवत: यह स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहने वाली है। खासकर विपक्षी गठबंधन में चेहरे की लड़ाई भले ही अभी नहीं हुई हो किन्तु चुनाव आते-आते इसका विस्फोट होना तय है अत: केंद्र की राजनीति को लेकर भाजपा अभी निश्चिंत है किन्तु प्रदेशों को लेकर वैसी निश्चिंतता भाजपा नेतृत्व को नहीं है।

पहले हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हाल ही में कर्नाटक जैसे दुर्ग ढहने के बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जनता के बीच यह संदेश नहीं देना चाहता कि प्रदेशों से भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक रही है। फिर मध्य प्रदेश गुजरात की ही भांति हिंदुत्व की प्रयोगशाला का बड़ा गढ़ है और 2018 में कमलनाथ सरकार ने डेढ़ साल के अपने संक्षिप्त कार्यकाल में ही इस प्रयोगशाला को नुकसान पहुंचा दिया था। जिस दूसरी सूची में भाजपा ने अपने केन्द्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है उस दूसरी सूची की 39 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटें भाजपा 2018 में हार गई थी और सरकार बनाने से चूक गई थी। ऐसे में बड़े केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वह इस बार कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना चाहती। हालांकि इस सूची के जारी होते ही कहीं-कहीं विवाद की स्थिति बन रही है। मसलन, नागदा से तेज बहादुर सिंह का विरोध होने लगा है, वहीं सीधी में वर्तमान विधायक केदारनाथ शुक्ला के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही केदारनाथ शुक्ला हैं जिनके खास समर्थक पर आदिवासी समुदाय के पुरुष पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा भितरवार से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा को ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मोहनसिंह राठौर के हाथों मायूसी मिली है तो सतना के विधायक नारायण त्रिपाठी की पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते छुट्टी हो गई है। दोनों स्थानों पर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं।

नरसिंहपुर में जालम सिंह पटेल के स्थान पर उनके बड़े भाई प्रह्लाद सिंह पटेल को टिकट देकर पार्टी ने क्षेत्र में पटेल परिवार की पारिवारिक मजबूती को स्वीकार किया है। बहरहाल, भाजपा की दूसरी सूची जारी होते ही जहां कई नेता पुत्र-पुत्रियों का राजनीति में स्थापित होने का सपना टूटा है वहीं पार्टी ने हिरेंद्र सिंह बंटी, ज्योति डहेरिया, नंदा ब्राह्मणे, नरेंद्र शिवाजी पटेल, मधु गहलोत, श्रीकांत चतुर्वेदी, पंकज टेकाम, गौरव पारधी, तेज बहादुर सिंह व श्याम बर्डे जैसे नए चेहरों को टिकट देकर क्षेत्र में एंटी-इन्कंबेंसी को भी रोकने की जद्दोजहद की है। इस दूसरी सूची ने भाजपा के भविष्य की राजनीति की झलक भी दे दी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में युवा प्रोफेशनल्स चुनाव लड़ते नजर आएंगे।

हालांकि कांग्रेस ने भाजपा की दूसरी सूची पर तंज कसते हुए इसे 15 वर्षों का कुशासन बताया है किन्तु कहीं-कहीं अब कांग्रेस पर भी दबाव है कि वे अपने राष्ट्रीय स्तर के चर्चित चेहरों जैसे दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, विवेक तन्खा, अजीज कुरैशी, कांतिलाल भूरिया को विधानसभा के रण में उतारे और भाजपा को कड़ी चुनौती पेश करे। फिलहाल भाजपा ने राज्य से जुड़े अपने केन्द्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर हाथ से फिसलते मध्य प्रदेश को कसकर पकड़े रखने का प्रयास किया है। वह इस प्रयास में सफल होती है या नहीं ये चुनाव परिणाम ही बतायेगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-3)

गतांक से आगे...

अन्त:स्थ होकर ध्यान करने से उनके ललाट से त्रिनेत्रयुक्त, हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस ऐश्वर्यशाली पुरुष के शरीर में यश, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, नियन्त्रित मन, श्री- सम्पन्नता एवं ओंकार सहित व्याइतियाँ, ऋ यजु: साम, अथर्व आदि चारों वेद तथा समस्त छन्द प्रतिष्ठित थे। इसी कारण वह ईशान एवं महादेव के नाम से प्रख्यात हुए।

इसके पश्चात् पुन: उन भगवान् नारायण ने अन्य कामना से अन्त: में स्थित होकर ध्यान किया। उस अन्त:स्थ ध्यान में लीन नारायण के ललाट से पसीने की बूँदें नि:सृत होने लगीं। वह पसीना ही चारों ओर फैलकर आप: (प्रकृति का मूल क्रियाशील द्रव्य) रूप में परिणत हो गया। उस आप से ही तेजोमय हिरण्यगर्भरूप अण्ड की उत्पत्ति हुई और उसी तेज से चतुर्मुख ब्रह्माजी प्रकट हुए। उन पितामह भगवान् ब्रह्माजी ने (चारों दिशाओं में भिन्न-भिन्न देवों का ध्यान किया। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके उन्होंने भू: व्याहृति, गायत्री छन्द, ऋग्वेद तथा अग्निदेव का ध्यान किया। पश्चिमाभिमुख होकर भुव: व्याहृति, त्रिष्टुप् छन्द, यजुर्वेद सहित वायुदेव का ध्यान किया। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर स्व: व्याहृति, जगती छन्द तथा सामवेद सहित सूर्य (सविता) देव का ध्यान किया और दक्षिण की तरफ अभिमुख होकर मह: व्याहृति, अनुष्टुप् छन्द तथा अथर्ववेद सहित सोम देवता का ध्यान किया। [यहाँ पितामह के द्वारा जिन-जिनके ध्यान करने का उल्लेख है, वे सभी उसी ध्यान प्रक्रिया से प्रादुर्भूत होते चले गये।]

जिन (विराट् पुरुष) के सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र हैं, जो सभी तरह से कल्याणकारी हैं, सर्वत्र संख्यास हैं, परात्पर हैं, नित्य हैं, सभी रूपों में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे उन भगवान् नारायण का ब्रह्माजी ने ध्यान किया। ये भगवान नारायण ही सम्पूर्ण विश्व के स्वरूप हैं, इन्हीं विराट् पुरुष पर समस्त जगत् का जीवन आश्रित है। ब्रह्माजी ने सम्पूर्ण जगत् के पालक, विश्वरूप, विश्वेश्वर को तथा क्षीर सागर में योगनिद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान् श्रीनारायण का ध्यानावस्था में दर्शन प्राप्त किया। जो पद्मकोश के सदृश, आकोश (सम्यक् रूप से विकसित कोश) के आकार में लम्बायमान एवं अधोमुख हृदय है, जिससे सतत सीत्कार शब्द नि:सृत होता रहता है। उस हृदय के मध्य में एक महान ज्वाला प्रदीप्त हो रही है। वहीं ज्वाला दीपशिखा की भाँति दसों दिशाओं में अविनाशी प्रकाश तत्त्व को वितरित करती हुई सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित कर रही है उसी ज्वाला के बीच में थोड़ी दूर ऊर्ध्व की ओर उठी हुई एक पतली सो वह्निशिखा स्थित है उसी शिखा के मध्य में उस विराट् पुरुष परमात्मतत्त्व का वास स्थल है। वे ही ब्रह्मा हैं, वहीं विष्णु एवं ईशान हैं और वही देवराज इन्द्र हैं। वे ही अविनाशी अक्षर एवं परम स्वराद भी हैं। यही महोपनिषद् है।

श्री गणेश विसर्जन

ललित गर्ग

गणेश चतुर्थी त्योहार को कई जगहों पर कलंक चतुर्थी, शिव चतुर्थी और डंडा चतुर्थी भी कहते है। बता दें कि गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश उत्सव की भी शुरुआत होती है जो कि अनंत चतुर्दशी तक जारी रहता है। यानी ये त्योहार पूरे 10 दिनों तक जारी रहता है। इस दौरान घर, मंदिर, पूजा पंडालों में भगवान गणेश की विधिवत स्थापना की जाती है। इस दौरान गणेश जी का विधिवत पूजन होता है। इसके बाद 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के मौके पर भगवान गणेश का विधिवत विसर्जन होता है। इस बार गणेश जी की मूर्ति का विधिवत विसर्जन 28 सितंबर को होगा। पंचांग के मुताबिक चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12.39 बजे से हुई। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 19 सितंबर 2023 को दोपहर 01.43 बजे हुई।

गणेश भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, वे विघ्नहर्ता एवं मंगलकर्ता सात्विक देवता हैं और उन्नत राष्ट्र-निर्माता हैं। वे न केवल भारतीय संस्कृति एवं जीवनशैली के कण-कण में व्याप्त है बल्कि विदेशों में भी घर-कारों-कार्यालयों एवं उत्पाद केन्द्रों में विद्यमान हैं। हर तरफ गणेश ही गणेश छाए हुए है। मनुष्य के दैनिक कार्यों में सफलता, सुख-समृद्धि की कामना, बुद्धि एवं ज्ञान के विकास एवं किसी भी मंगल कार्य को निर्विघ्न सम्पन्न करने हेतु गणेशजी को ही सर्वप्रथम पूजा जाता है, याद किया जाता है। प्रथम देव होने के साथ-साथ उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, लोकनायक का चरित्र हैं। गणेश शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं, ऐसे सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सार्वदैशिक लोकप्रियता वाले देव का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सम्पूर्ण दुनिया में उमंग एवं हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गणेशोत्सव हिन्दुओं का एक उत्सव है। महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

हिन्दुओं में गणेशजी के जन्म के विषय में अलग-अलग कथाएँ प्रचलित हैं। वराह पुराण के अनुसार स्वयं शिव ने पंच तत्त्वों को मिला कर गणेश का निर्माण बहुत तन्मयता से किया। जिससे वे अत्यंत सुन्दर और आकर्षक बने तो देवताओं में खलबली मच गयी, स्थिति को भांप कर शिव ने गणेश के पेट का आकार बढ़ा दिया और सिर को गजानन की आकृति का कर दिया ताकि उनके सौन्दर्य और आकर्षण को कम किया जा सके। शिव पुराण के अनुसार एक बार पार्वती ने अपने उबटन के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें जीवन डाल दिया। इसके उपरांत उन्होंने इस जीवधारी पुतले को द्वार पर प्रहरी के रूप में बैठा दिया और उसे आदेश दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को अंदर न आने दे। इसके बाद वे स्नान करने लग गई। संयोगवश कुछ ही समय बाद शिव उधर आ निकले। उनसे सर्वथा अपरिचित गणेश ने शिव को भी अंदर जाने से रोक दिया। इस पर शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। पार्वती ने यह देखा तो वे बहुत दुखी हुईं। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। तभी से गणेश, गजानन कहलाए। लेकिन बालक की आकृति से पार्वती बहुत दुखी हुई तो सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद और अतुलनीय उपहार भेंट किए, उन्हें प्रथम देव के रूप में सभी अधिकार प्रदत्त किये। इंद्र ने अंकुश, वरुण ने पाश, ब्रह्मा ने अमरत्व, लक्ष्मी ने ऋद्धि-सिद्धि और सरस्वती ने समस्त विद्याएँ प्रदान कर उन्हें देवताओं में सर्वोपरि बना दिया। गणेशजी को प्रथम लिपिकार माना जाता है उन्होंने ही देवताओं की प्रार्थना पर वेद व्यासजी द्वारा रचित महाभारत को लिपिबद्ध किया था। जैन एवं बौद्ध धर्मों में भी गणेश पूजा का विधान है। गणेश को हिन्दू संस्कृति में आदिदेव भी माना गया है।

क्या कनाड़ा की धरती पर बनेगा खालिस्तान?

अशोक मधुप

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में खालिस्तान बनाने की मांग करने वाले अतिवादियों पर पूरी तरह मेहरबान है। भारत द्वारा इन अतिवादियों के बारे में दी गई जानकारी पर वे कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, अपितु भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भारत से फरार अपराधी खालिस्तानी अतिवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उसके राजनयिक का हाथ है। भारत को चाहिए कि यह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के खालिस्तान का समर्थन करने वाले अतिवादियों का समर्थन करने दें। कुछ समय ऐसा ही चलने दें। हां सार्वजनिक रूप से भारत उसे चेतावनी देने का सिलसिला जारी रखें। अपने यहां खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती रखें। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा तो यह निश्चित है कि अब खालिस्तान भारत में नहीं कनाडा में बनेगा। कनाडा की धरती पर बनेगा। आज जो कनाड़ा कर रहा है, कभी वही भारत के कुछ नेताओं ने किया था। वह पंजाब में खालिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को नजर अंदाज करते रहे। परिणाम स्वरूप पजांब में रहने वाले हिंदुओं को पंजाब छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। उन पर हमले होने शुरू हो गए। सिख आंतकवाद पंजाब में ही नही बढ़ा, अपितु उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को भी उसने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। इस दौरान पंजाब में धार्मिक नेता भिंडरावाला तेजी से लोकप्रिय होने लगे। कहा जाता है कि राजनैतिक लाभ के लिए केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसे प्रश्य देना शुरू कर दिया। हालत यह हुई कि वहीं भिंडरावाला कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हुआ। उसने स्वर्ण मंदिर में डेरा जमा लिया। मजबूरन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भिंडरावाला को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए फौज का सहारा लेना पड़ा। बाद में उनके ही दो सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी।

आज जो कनाडा में हो रहा है, वह 40 साल से खालिस्तान समर्थकों को पोषित किए जाने का परिणाम है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलन पिछली सदी के आठवें दशक में शुरू हो गया था। पियरे ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी जड़ें गहरी हुईं। उनके कार्यकाल के दौरान ही तलविंदर परमार भारत में चार पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद कनाडा भाग गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जून 1973 में कनाडा की यात्रा की थी और पियरे ट्रूडो के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध सौहार्दपूर्ण थे। लेकिन, पियरे ट्रूडो ने 1982 में तलविंदर परमार को भारत प्रत्यर्पित करने का अनुरोध ठुकरा दिया। इसके लिए बहाना बनाया गया कि भारत का रुख महारानी के प्रति पर्याप्त रूप से सम्मानजनक नहीं है। पियरे ट्रूडो के पद छोड़ने के ठीक एक साल बाद तलविंदर परमार ने जून 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 (कनिष्क) में बम विस्फोट की साजिश रची, जिसमें विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए। हालाकि मरने वालों मे अधिकतर कनाडा के ही नागरिक थे।इस विमान हादसे में कुछ तो पूरे परिवार ही खत्म हो गए।

अगर पियरे ट्रूडो ने तलविंदर परमार को भारत प्रत्यर्पित करने का इंदिरा गांधी का अनुरोध मान लिया होता, तो कनिष्क विमान में विस्फोट नहीं हुआ होता। भारतीय-कनाडाई राजनीति के जानकार मानने लगे हैं कि जो गलती पियरे ट्रूडो ने तब की थी, वहीं उनके बेटे जस्टिन ट्रूडो भी आज कर रहे हैं। अपनी सरकार चलाने के लिए कनाडा में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों के प्रति सहानुभूति रखकर वही गलती कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर कनाडा में पल रहे खालिस्तानी समर्थकों को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री के इन आरोपों के बाद कनाडा के अलग-अलग राज्यों में खालिस्तान समर्थकों ने ऐसी साजिश रचनी शुरू कर दी जिससे वहां रह रहे न सिर्फ भारतीयों बल्कि डिप्लोमेट्स और भारतीय दूतावास के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है बल्कि कनाडा में बसे भारतीय हिंदुओं को भी खतरा बनेगा। खालिस्तानी समर्थकों ने 25 सितंबर को कनाडा के हाईकमीशन और सभी काउंसलेट के बाहर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर पता चला है कि ब्रिटिश कोलंबिया के सरे स्थित गुरुद्वारे में काउंसिल के कुछ सदस्यों ने इसे लेकर साजिश रची है। जानकारी यह भी है कि इस पूरे प्रदर्शन में कनाडा के कई पूर्व सांसद, नेता और कुछ चरमपंथी और खालिस्तान समर्थक इस मामले पर खतरनाक मंसूबों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा की जमीन पर पहले से ही खालिस्तान समर्थकों को कनाडा की सरकार प्रश्रय देती आई है। यही वजह है कि कनाडा सरकार के समर्थन के चलते भारत विरोधी गतिविधियां इस देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार चलती रहती हैं। बीते कुछ समय में खालिस्तान जनमत संग्रह के नाम पर कनाडा की सरकार न सिर्फ इन भारत विरोधी खालिस्तानियों को सुरक्षा मुहैया कराती आई है बल्कि कार्यक्रम स्थलों की भी उपलब्ध करवाती आई है।

पिछले दिनों एक शोभा यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया है उसका असर अगले कुछ दिनों में ही बहुत तेजी से दिखाना शुरू हो सकता है। विदेशी मामलों की जानकार मानते हैं कि कनाडा सरकार का भारत के लिए लिया गया एक्शन आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी बड़ा असर डालने वाला है। कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान के बाद के हालात में क्रम में सिख फॉर जस्टिस (स्वच्छ) के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से हिंदू समुदाय को धमकी दी गई है।

हिन्द स्वराज्य

इटली और हिन्दुस्तान

प्रश्न- इटली ने किया वैसे। मैजिनी और गैरीबाल्डी ने जो किया, वह तो हम भी कर सकते हैं। वे महावीर थे, इस बात से क्या आप इन्कार कर सकेंगे?

उत्तर- आपने इटली का उदाहरण ठीक दिया। मैजिनी महात्मा था। गैरीवाल्डी बड़ा योद्धा था। दोनों पूजनीय थे। उनसे हम बहुत सीख सकते हैं। फिर भी इटली की दशा और हिन्दुस्तान की दशा में फरक है। पहले तो मैजिनी और गैरीबाल्डी के बीच का भेद जानने लायक है। मैजिनी के अरमान अलग थे। मैजिनी जैसा सोचता था वैसा इटली में नहीं हुआ। मैजिनी ने मनुष्य जाति के कर्तव्य के बारे में लिखते हुए यह बताया है कि हर एक को स्वराज्य भोगना सीख लेना चाहिए। यह बात उसके लिए सपने जैसी रही। गैरीबाल्डी और मैजिनी के बीच मतभेद हो गया था, यह हमें याद रखना चाहिए। इसके सिवा, गैरीबाल्डी ने हर इटालियन के हाथ में हथियार दिये और हर इटालियन ने हथियार लिये। इटली और आस्ट्रिया के बीच सभ्यता का भेद नहीं था। वे तो चचेरे भाई माने जायेंगे। जैसे को तैसा वाली बात इटली की थी। इटली को परदेशी (आस्ट्रिया के) जूए से छुड़ाने का मोह गैरीबाल्डी को था। इसके लिए उसने कावूर के मारफत जो साजिशें कीं, वे उसकी शूरता को बट्टा लगाने वाली हैं। और अन्त में नतीजा क्या निकला? इटली में इटालियन राज करते हैं इसलिए इटली की प्रजा सुखी है, ऐसा आप मानते हों तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अँधेरे में भटकते हैं। मैजिनी ने साफ-साफ बताया है कि इटली आजाद नहीं हुआ है। विक्टर इमेन्युअल ने इटली का एक अर्थ किया, मैजिनी ने दूसरा। इमेन्युअल, कावूर और गैरीबाल्डी के विचार से इटली का अर्थ था इमेन्युअल या इटली का राजा और उसकी हुजूरी। मैजिनी के विचार से इटली का अर्थ था इटली के लोग—उसके किसान। इमेन्युअल वगैरा तो उनके (प्रजा के) नौकर थे। मैजिनी का इटली अब भी गुलाम है। दो राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगी थी; इटली की प्रजा तो सिर्फ प्यादा थी और है।

क्रमश: ...

राजस्थान में वसुंधरा नहीं तो कौन?

अंकित सिंह

राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने है। भाजपा अपनी तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की भूमिका पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। जयपुर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने संकेत दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महत्वपूर्ण राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना जा सकती है। गुलाबी शहर में पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने संकेत दिया कि राज्य में आने वाले चुनावों में भाजपा का प्रतीक कमल पार्टी का चेहरा होगा। खबर यह भी है कि राजस्थान में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज रात जयपुर में होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन होगी।

पीएम मोदी के जयपुर आगमन पर दो बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक आगामी चुनाव के लिए पार्टी के चेहरे के रूप में उनके नाम की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी चेहरे के नाम पर तस्वीर साफ करने के बजाय, पीएम ने संकेत दिया कि बीजेपी मोदी और पार्टी चिन्ह (कमल) को पार्टी का चेहरा बनाकर चुनाव में जा सकती है, जिससे सीएम पद के लिए अगले उम्मीदवार पर चल रहा सस्पेंस और गहरा हो गया है। अतीत में, भाजपा ने यह रणनीति तब अपनाई थी जब उसे लगा कि चुनाव से पहले नाम चुनने से पार्टी में विभाजन हो सकता है। भगवा पार्टी यह रणनीति तब अपनाती है जब उसे लगता है कि स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में राज्य इकाई प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और पार्टी पीएम मोदी को चेहरे के रूप में पेश करती है। इस बीच सीएम उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी आलाकमान की चुप्पी भी इस बात का सबूत है कि राजस्थान में पार्टी इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है।

कई मीडिया रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि पार्टी दो गुटों में विभाजित है - राजे के नेतृत्व वाला समूह और केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले दो दिनों से अपने गृह क्षेत्र झालावाड़ और कोटा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा से गायब थीं। पीएम मोदी के दौरे से पहले राजे का यह बयान कि वह राजस्थान नहीं छोड़ेंगी। राजे गाथा का संबंध राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार कहा था कि जब उनकी पार्टी के प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट ने उनकी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था तो राजे ने उनकी मदद की थी। इसके अलावा, पायलट ने कई मौकों पर गहलोत पर राजे सरकार के दौरान कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दरअसल, पायलट ने राजे शासन के भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिवसीय मौन धरना दिया। शायद राजे पर गहलोत का कथित नरम रुख राजस्थान बीजेपी में विवाद की जड़ बन गया।

अपने आसपास के तमाम विवादों और अपनी सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद, राजे के दावे को भाजपा में कम नहीं आंका जा सकता है। उनके पास कांग्रेस और गहलोत के खिलाफ चुनावी जीत की विरासत है जो उन्हें सीएम पद के लिए सबसे आगे बनाती है। उनके नेतृत्व में, भाजपा ने 2003 और 2013 में गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस को हराया। वह राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव रखती हैं। पिछले चुनावों में उन्होंने राज्य में जातिगत समीकरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। राजे अच्छी तरह जानती हैं कि चुनावी सफलता हासिल करने के लिए जाति कार्ड कैसे खेला जाता है। वह खुद को जाटों की बहू, राजपूतों की बेटी और गुज्जरों की समधन कहती थी। हालाँकि, पार्टी में अंदरूनी कलह को भांपते हुए, कुछ महीने पहले भाजपा ने उनके कथित प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र राठौड़ को राजस्थान विधानसभा में एलओपी बनाकर पदोन्नत किया था। राठौड़ राजपूत समुदाय से हैं। इस घटनाक्रम ने राजे गुट को परेशान कर दिया था और इस फैसले को जाति-समीकरण संतुलन के कदम के रूप में देखा गया था। लेकिन ये बात भी सच है कि राजे के पक्ष में हमेशा पार्टी के ज्यादातर विधायकों का समर्थन रहा है।

जैसा कि भाजपा ने संकेत दिया है कि वह राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की लहर पर सवार हो सकती है, ऐसे में राजे के लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य इकाई के प्रमुख चंद्र प्रकाश जोशी, राजेंद्र राठौड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कुछ ऐसे नाम हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में, भाजपा चुनावी मौसम में भी राजे को दरकिनार करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। इसलिए वह पार्टी के पोस्टर और बड़े कार्यक्रमों पर मौजूद रहती है।

वर्तमान में देखें तो भाजपा ज्यादातर राज्यों में बिना किसी चेहरे के ही चुनावी मैदान में उतर रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद से भाजपा ने किसी भी राज्य में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। बावजूद इसके उसे कई राज्यों में सफलता जरूर मिली है। राजस्थान में भी भाजपा इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश में है। देखना होगा उसे जनता का कितना समर्थन मिलता है। यही तो प्रजातंत्र है।

महिला आरक्षण बनाम ओबीसी: भाजपा कांग्रेस में किसका सफल होगा दांव?

संतोष पाठक

महिला आरक्षण बिल की सुगबुगाहट के साथ ही कांग्रेस ने ओबीसी राग आलापना शुरू कर दिया था। लोकसभा में विपक्षी दलों की पहली स्पीकर के तौर पर बोलते हुए कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को अपने पति और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना बताने के साथ-साथ भारत सरकार से जाति जनगणना करा कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण देकर आगे बढ़ाने की मांग की। हालांकि कोटे के अंदर कोटे की नीति के तहत सरकार ने अपने महिला आरक्षण बिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव शामिल कर रखा है लेकिन ओबीसी समुदाय की महिलाओं को आरक्षण देने पर सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है कि अभी संविधान में सामान्य वर्ग के साथ-साथ सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है इसलिए इससे अलग हटकर कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में उठाए गए ओबीसी गणना और आरक्षण के मुद्दें का राज्यसभा में जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के जितने सांसद हैं, उससे ज्यादा तो लोकसभा में उनके ओबीसी सांसद हैं। नड्डा ने कहा कि भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा ने दिया। भाजपा के 85 लोकसभा सांसद ओबीसी समाज से हैं। भाजपा के 27 फीसदी विधायक और 40 फीसदी एमएलसी भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। दरअसल, सच्चाई यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल महिला मतदाताओं के साथ-साथ ओबीसी वोटरों का महत्व बखूबी समझते हैं। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि आमतौर पर महिला वोटर जातियों की सीमा से परे जाकर अन्य मुद्दों पर वोट करते हैं यानी महिला वोटर ईवीएम का बटन दबाते समय पुरुष वोटरों की तरह सिर्फ जाति के बारे में ही नहीं सोचते हैं। इसलिए भाजपा ने महिला वोटरों को लेकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। भाजपा को यह लगता है कि ओबीसी समुदाय को उन्होंने अब तक बहुत कुछ दिया है और आने वाले दिनों में भी उनके पास देने को बहुत कुछ है। भाजपा को यह भी लग रहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल पास करवाने का दांव सही से चल गया तो देश के चुनावी इतिहास में भाजपा न केवल अपना रिकार्ड तोड़ सकती है बल्कि 1984 के राजीव गांधी के रिकार्ड को भी पार कर सकती है। इसलिए भाजपा आने वाले दिनों में जोर-शोर से महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की मतदाताओं के पास जाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रही है। दूसरी तरफ, नरेंद्र मोदी को 2024 में किसी भी कीमत पर हराने के लिए बेताब कांग्रेस महिला वोटरों के साथ-साथ ओबीसी वोटरों पर भी दांव खेलने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह लड़ाई कांग्रेस से ज्यादा उसके आरजेडी और सपा जैसे सहयोगी दलों की ज्यादा लग रही है। देश के महिला वोटरों और प्रभावशाली ओबीसी तबको को छोड़ कर ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अन्य जातियों में भाजपा खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह लग रहा है कि इसमें सेंध लगाए बिना मोदी को हराना नामुकिन है इसलिए कांग्रेस ने एक साथ कई स्तरों पर अभियान छेड़ दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यह कह रहे हैं कि सत्ता में आते ही वह तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण को लागू कर देंगे और साथ ही जाति जनगणना करवा कर ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण का रास्ता भी खोलेंगे। जाहिर है कि एक तरफ भाजपा है जिसे महिला आरक्षण के अपने दांव पर पूरा भरोसा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो महिला वोटरों को लुभाने के साथ ही जाति जनगणना की मांग के जरिए ओबीसी वोटरों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में फिलहाल तो भाजपा और कांग्रेस की यह चुनावी जंग महिला आरक्षण बनाम ओबीसी के दांव में ही बदलती हुई ज्यादा नजर आ रही है।

उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकती है सपा

रोहित मिश्र

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं सीटों को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति बनाने लगी हैं। सबसे ज्यादा हलचल इंडिया गठबंधन के खेमे में है। सभी की दिलचस्पी इस बात में है कि सपा, कांग्रेस और रालोद के लिए कौन-कौन सी सीटें छोड़ती है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी उन लोकसभा सीटों को इंडिया गठबंधन के घटक दलों को पहले छोड़ सकती है, जहां उसे कभी विजय नहीं मिली। इस तरह की उत्तर प्रदेश में करीब 19 सीटें हैं। इन पर सपा इसलिए भी दावा नहीं करेगी, क्योंकि इनमें से कई सीटों पर घटक दलों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव सपा ने बसपा के साथ मिलकर लड़ा था। सपा नेताओं का मानना है कि उस चुनाव में जौनपुर, मऊ और अंबेडकरनगर सरीखी अधिक संभावना वाली सीटें बसपा के लिए चली गई थीं, जबकि लखनऊ और वाराणसी सरीखी वो सीटें सपा के हिस्से में आईं, जहां वह कभी जीती ही नहीं। इसलिए इस बार गठबंधन के तहत सपा उन सीटों को पहले देगी, जहां उसे अपने जन्म से लेकर आज तक कभी सफलता नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक, इस तरह की करीब 19 सीटें चिह्नित भी की गई हैं। ये हैं-बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, बरेली, कानपुर, पीलीभीत, धौरहरा, गोंडा, बस्ती, वाराणसी, सुल्तानपुर और लखनऊ। इसके अलावा अमेठी व रायबरेली में राजनीतिक शिष्टाचार के तहत सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती रही है, क्योंकि यहां से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। यहां बता दें कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। शीघ्र ही राज्यवार मंथन किया जाएगा। कांग्रेस और सपा के बीच पिछले कुछ समय से सीटों को लेकर गर्मजोशी वाले बयान नहीं आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन को सीटें देंगे ना कि उसने मांगेंगे। इसका साफ मतलब यह है कि यूपी सपा अपने अनुसार ही टिकट बांटने की बात कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस बसपा के साथ भी बातचीत कर रही है। सूत्रों के अनुसार मायावती और प्रियंका गांधी की इस मसले पर एक-दो बार मुलाकात हो चुकी है। इसके साथ-साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यह बात कई बार दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस सभी सीटों को लड़ने के हिसाब से तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन में वैसे तो रालोद भी है लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस का दावा ज्यादा मजबूत है। पश्चिम यूपी की कुछ सीटों को छोड़कर बाकी पूरे यूपी में सपा और कांग्रेस ही आपस में सीटें बांट सकती हैं।

इस कड़वाहट के लिए पूरी तरह ट्रूडो जिम्मेदार

राजेश बादल

अब यह साफ हो गया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्ता में बने रहने के लिए अपने राष्ट्र के हितों और अंतरराष्ट्रीय मान्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ताक में रख दिया है। वे घोषित आतंकवादियों को बचाने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें एक लोकतांत्रिक देश की संप्रभुता, मानवीय मूल्य याद नहीं आते। यदि उनका यह व्यवहार उचित मान लिया जाए तो जब अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान में खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा, तब कनाडा ने अमेरिका का विरोध क्यों नहीं किया? अमेरिका के इस प्यारे पड़ोसी को पाकिस्तान की संप्रभुता की चिंता नहीं हुई। यही नहीं, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को जिस तरह मारा गया, वह क्या इराक की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं था? इराक के बारे में जो खुफिया सूचनाएं इन पांच देशों ने साझा की थीं, क्या वे गलत साबित नहीं हुईं ? क्या यह सच नहीं है कि खालिस्तान के लिए कनाडा और ब्रिटेन की धरती से पृथकतावादियों और उग्रवादियों को दशकों से प्रोत्साहन दिया जाता रहा और भारत के ढेरों विरोध पत्रों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया? जस्टिन ट्रूडो के पिता भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में खालिस्तानी उग्रवादी संगठनों को पनाह दी जाती रही। इसका अर्थ यही है कि वर्तमान कनाडाई प्रधानमंत्री अपने पिता पियरे ट्रूडो की राह पर चल पड़े हैं और उग्रवादियों के दबाव में काम कर रहे हैं।

हालांकि पियरे उग्रवादियों के दबाव में नहीं थे, पर उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। उस दौर में अमेरिका, कनाडा और काफी हद तक ब्रिटेन का रुख पाकिस्तान के पक्ष में झुका था. सोलह साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए पियरे ट्रूडो भारत विरोधी तत्वों को भरपूर समर्थन देते रहे। दरअसल जस्टिन की सरकार खालिस्तान का खुल्लमखुल्ला समर्थन करने वाले न्यू डेमोक्रेटिक दल की

बैसाखी पर टिकी हुई है। यह दल जगमीत सिंह की अगुआई में चल रहा है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी अल्पमत में थी और इस न्यू डेमोक्रेटिक दल ने समर्थन दिया तो जस्टिन ने सरकार बनाई। कनाडा की संसद में 338 सीट है। पिछले चुनाव के बाद जस्टिन की पार्टी के पास केवल 157 सांसद हैं। उनके पास बहुमत नहीं होने से खालिस्तान समर्थक पार्टी के सांसदों से समर्थन लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ।

कंजर्वेटिव पार्टी को केवल 121 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा. अब अगले चुनाव 2025 में होने हैं और जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में बेहद गिरावट आई है। बेशक पहला निर्वाचन उनके लिए बहुमत लेकर आया था, मगर बाद में वे चुनाव दर चुनाव जनाधार खोते गए। भारत के साथ रिश्तों में तल्खी के बाद तो वे मुल्क में अपनी छवि बिगाड़ बैठे हैं। ऐसे में खालिस्तान समर्थक सियासी पार्टी का साथ लेना उनकी मजबूरी भी है। यूं तो अमेरिका के साथ भी उनके कार्यकाल में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति थे तो ट्रम्प ने उन्हें बेईमान और कमजोर बताया था। कनाडा की संसद ने ट्रूडो पर निजी आक्रमण के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था। उन्हें कनाडा की नैतिकता आयुक्त ने अनैतिक कृत्य के लिए दोषी पाया था। ट्रूडो बहामा के द्वीप पर अपने एक मुस्लिम अरबपति मित्र के न्यौते पर सपरिवार सैर सपाटे के लिए गए थे। इसका कनाडा में बड़ा विरोध हुआ था। वहां के कानून के मुताबिक कोई प्रधानमंत्री इस तरह का उपकार नहीं ले सकता। ट्रूडो इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से माफी मांग चुके हैं।

मौजूदा बरस कनाडा और भारत के लिए बेहद कड़वाहट भरा बीत रहा है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार हैं। भारत के विरोध को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। इस साल की कुछ घटनाएं इसकी बानगी हैं। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार की तारीख को वहां भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी सड़कों पर निकाली गई। इसी महीने में वहां के सुरक्षा सलाहकार ने साफ-साफ आरोप लगाया कि भारत उनके देश में हस्तक्षेप कर रहा है। जून में ही खालिस्तानी आतंकवादी और भगोड़े हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। बताया जाता है दो गुटों की आपसी रंजिश के कारण हत्या हुई। लेकिन कनाडा ने इसके पीछे भारत का हाथ बताया। भारत ने जुलाई में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और कहा कि अपने देश में भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियां रोकें। कनाडा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद समूह-20 की बैठक के बाद जस्टिन ट्रूडो का रवैया किसी से छिपा नहीं रहा। बेहद आक्रामक मुद्रा में ट्रूडो नजर आए और भारत के साथ उन्मुक्त कारोबार की प्रक्रिया स्थगित कर दी। ट्रूडो संसद में निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताते हैं और एक राजनयिक को अपने देश से निकाल देते हैं। जवाब में भारत ने भी यही उत्तर दिया। अब ट्रूडो सारे गोरे देशों से समर्थन मांग रहे हैं, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। इस मामले में ब्रिटेन ने तो उलटे झटका दिया। उसने न केवल भारत के समर्थन में खुलकर बयान दिया, बल्कि 22 पाकिस्तानियों को भारत विरोधी हिंसा के लिए दोषी माना। अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ब्रिटेन के लेस्टर में अब घर-घर सर्वेक्षण हो रहा है और वहां रहने वालों के बारे में कड़ी जांच हो रही है।

सफल आयोजन पर भी सवाल क्यों?

संजय तिवारी

सरकार के स्तर पर कितना भी सफल आयोजन हो, उसमें कोई कमी न हो तो भी विपक्ष को उसमें कुछ न कुछ कमी ही निकालनी होती है। कुछ ऐसा ही इस समय नई दिल्ली में आयोजित जी20 के सफल आयोजन के बाद दिख रहा है। अगर यह आयोजन किसी तरह से असफल होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन सफल हुआ तो क्यों सफल हुआ, इस तरह के सवाल उठाये जा रहे हैं। मसलन, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यही सवाल उठा दिया कि विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में छप्पन भोग परोसा गया जबकि देश के करोड़ों लोग हैं जो पांच किलो अनाज के भरोसे हैं। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। तो राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि इस पर इतना पैसा खर्च किया गया इससे देश की जनता को क्या मिलेगा? शरद पवार ने वैसे तो आयोजन पर सवाल नहीं उठाया लेकिन ये जरूर पूछा कि पहली बार इस तरह के आयोजन में चांदी सोने के चम्मच प्लेट इस्तेमाल किये गये। लेकिन इनमें सबसे महत्पूर्ण है राहुल गांधी का सवाल। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भारत सरकार हमारे गरीब लोगों और जानवरों को छुपा रही है। हमारे मेहमानों से भारत की हकीकत छुपाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी का इशारा संभवतः उस फोटो की ओर है जिसे जी20 आयोजन से पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल किया गया था। इस फोटो में एक जनता कालोनी को टाट की दीवार से ढका हुआ दिखाया गया था। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करनेवालों ने बताया कि दिल्ली के जी20 सम्मेलन में इस तरह से गरीबों की बस्ती को ढंक दिया गया है।

हालांकि सोशल मीडिया पर फोटो वॉयरल होने के बाद पीआईबी ने इस फोटो का फैक्ट चेक किया कि ये फोटो जी20 के आयोजन से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि मुंबई का है। उस पर फोटोशॉप के जरिए जी20 का पोस्टर लगाकर दिल्ली का बता दिया गया था। इस सच्चाई के बावजूद भी अगर राहुल गांधी जी20 के आयोजन में गरीब लोगों को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं तो यह राजनीतिक रूप से ही अप्रासंगिक हो जाता है। निश्चय ही राहुल गांधी भारत की जिस सच्चाई को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं उसे छिपाया भी नहीं गया है। इंदिरा गांधी के समय से गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा है तो क्या देश में गरीबी खत्म हो गयी? 140 करोड़ लोगों के देश में पूंजी का असमान बंटवारा एक समस्या है लेकिन क्या उस समस्या का कोई रिश्ता जी20 के आयोजन से जुड़ता है? इसके उलट प्रधानमंत्री मोदी ने जीडीपी केन्द्रित विकास की बजाय मानव केन्द्रित विकास की जो बात कही है वह कहीं न कहीं पूंजी के इसी असमान बंटवारे को समाप्त करने की पहल हो सकती है।

जीडीपी और पर कैपिटा इन्कम निर्धारित करने का जो वर्तमान वैश्विक तरीका है वह तरीका ही दोषपूर्ण है। एक देश की समग्र आय को समग्र जनसंख्या में समान बंटवारा करके उसका एक औसत निकाल लेना देश की कुल आर्थिक हालत तो बयान करता है लेकिन असमान पूंजी बंटवारे की समस्या को दूर नहीं करता। अगर प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर जी20 जैसे ताकतवर

आर्थिक मंच पर मानव केन्द्रित आर्थिक विकास पर आगे भी काम जारी रहता है तो हो सकता है भविष्य में कोई नया तरीका विकसित हो। अभी तो विश्व के मानक वही हैं जो अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक पर समान रूप से लागू होते हैं। सोशल मीडिया पर ही एक और अफवाह उड़ायी गयी कि इस आयोजन पर निर्धारित बजट से 300 प्रतिशत अधिक खर्च किया गया। संकेत गोखले ने ट्वीट किया कि जी20 के आयोजन के लिए 990 करोड़ रूपये निर्धारित थे लेकिन इस पर कुल 4100 करोड़ रूपये खर्च किये गये। यह निर्धारित बजट से 300 प्रतिशत अधिक था। इस पर भी पीआईबी फैक्ट चेक ने सफाई दी कि जो अतिरिक्त खर्च बताया जा रहा है वह पर्मानेन्ट एसेट क्रियेशन पर है जिसका उपयोग सिर्फ जी20 तक सीमित नहीं है। आगे भी इन संसाधनों का इस्तेमाल होगा। स्वाभाविक है इसमें भारत मंडपम का निर्माण भी शामिल होगा जिसकी लागत 2700 करोड़ रूपये बतायी जा रही है।

जी20 की बैठक हो या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन। वैश्विक आयोजनों का अपना एक मानक होता है और उस मानक से नीचे उतरकर आप उस आयोजन को नहीं कर सकते। ऐसे आयोजनों के समय में उस शहर को साफ सुथरा किया जाता है जहां इससे जुड़े आयोजन होने होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के समय में दिल्ली शहर में एक लाख करोड़ रूपये का निवेश किया गया था जिसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार भी हुआ। फिर भी इस आयोजन ने दिल्ली शहर को एक नया स्वरूप दिया जिसके लिए आज भी लोग दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही जी20 की बैठक से पहले दिल्ली ही नहीं हर उस शहर को सजाया और संवारा गया जहां इससे जुड़ी बैठकें सालभर होती रहीं। बनारस, श्रीनगर, जयपुर हर शहर में राज्य सरकारों ने अपने खर्चे से उस शहर में स्वच्छता और सुन्दरता का अभियान चलाया क्योंकि वहां जी20 देशों के प्रतिनिधि पहुंचने वाले थे। तो क्या यह सवाल उठाया जा सकता है कि राज्य सरकारों ने जी20 की बैठकों के लिए शहर को सजाने पर जो पैसा %बर्बाद% किया उसका उस शहर के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा?

किसी शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत होता है तो इसका दीर्घकालिक लाभ वहां रहनेवाले लोगों को ही मिलता है। इसलिए ऐसे सवाल ही बेमतलब और गुमराह करनेवाले हैं कि वैश्विक आयोजनों पर सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च करके सरकार अपनी वाहवाही करवाती है और जनता का पैसा बर्बाद करती है। सच्चाई तो यह है कि ऐसे आयोजनों के समय शहर के ढांचागत विकास पर जो पैसा खर्च होता है उसका स्थाई लाभ वहां रहनेवाली जनता को ही मिलता है। फिर जी20 की अध्यक्षता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिसका दीर्घकालिक लाभ केवल आर्थिक निवेश के रूप में ही नहीं बल्कि पर्यटन को बढावा देने वाला भी साबित होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित नवनिर्मित भारत मंडपम से ही मोदी सरकार ने न केवल भारत की सांस्कृतिक विविधता का परिचय करवाया बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के रूप में जी20 के सदस्य देशों के रूप में प्रस्तुत किया। यह नरेन्द्र मोदी ही हैं जिन्होंने सबसे मुखर रूप से भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में बताने की एडवोकेसी शुरु की। जी20 के आयोजन में इसकी झलक दिखाई दी। अब किसी दल या दल समर्थक को इन बातों से आपत्ति हो तो अलग बात है वरना जी20 के सफल आयोजन से भारत की गरिमा विश्व बिरादरी में बढ़ी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जी20 के सफल आयोजन के जरिए विश्व बिरादरी को कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो संदेश दिया है उसकी प्रशंसा आलोचक देश भी कर रहे हैं। ऐसे में यह समझना सचमुच मुश्किल है कि हमारे विपक्षी दलों को परेशानी क्यों हो रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना इसलिए सवाल उठा रहे हैं या फिर तकलीफ कुछ और है?

अच्छा सोचें और सिर दर्द घटाएं

सरदर्द, आज की जीवनशैली में होने वाली सबसे आम समस्या है और इसका कारण तनाव से लेकर माइग्रेन तक हो सकता है। तनाव की स्थिति में गर्दन की मांस पेशियों में सिकुड़न हो जाती है। शायद आपको यह आश्चर्यजनक लगे कि, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव लाकर आप सरदर्द से बच सकते हैं। अगर आपके सरदर्द का कारण भी तनाव है, तो तनाव का मुकाबला करना सीखें।

साफ हवा सुधारती है बच्चों के फेफड़ों की सेहत

साफ हवा में सांस लेना अमूमन सभी के लिए सेहतमंद माना जाता है, लेकिन बच्चे के लिए एक और भी फायदेमंद है। ताजा शोध के मुताबिक साफ हवा बच्चे के फेफडे की बेहतर सेहत के लिए लाभदायक है। शोध के अनुसार बच्चे के आसपास साफ हवा मुहैया कराने की कोशिश बचपन में उसके फेफडे की सेहत के लिए अच्छा तो है ही, यह भविष्य में भी उसके लिए फायदेमंद रहता है।

डायलिसिस से बचा सकती है स्टेम सेल थैरेपी

शोधकर्ताओं ने ऐसी चिकित्सा पद्धति ईजाद की है, जिसके प्रयोग से डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की स्थिति से बचा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पहली बार एंटी स्कैरिंग एजेंट के साथ स्टेम सेल थैरेपी के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके माध्यम से किडनी के क्षतिग्रस्त होने के संकेतों को बदलना संभव है। परिपक्व स्टेम सेल सेरेलेक्सिन प्रोटीन से मिलकर क्षतिग्रस्त किडनी को ठीक कर सकता है।

स्पेशल ट्रीटमेंट

कब होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत...

बीते कुछ वर्षों में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की प्रक्रिया काफी प्रचलित हो गई है। केवल अमेरिका में ही हर साल लगभग 600,000 लोगों की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है। भारत में भी इसका आंकड़ा काफी बड़ा है। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि आपको वाकई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत है। क्योंकि नी रिप्लेसमेंट से कई जोखिम भी जुड़े होते हैं। इसलिए आपके लिए ये जानना जरूरी होता है कि सर्जरी में कुछ गड़बड़ होने पर आपको किन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने से पहले जान लेने वाली 5 बेहद जरूरी बातें -

रिप्लेसमेंट सर्जरी के साइड इफेक्ट: डॉक्टरों के अनुसार घुटनों में अर्थराइटिस होने या फिर किसी चोट आदि से कई बार बेहद मुश्किल स्थिति पैदा हो जाती है और बेहद दर्द होने लगता है। और फिर जैसे-जैसे घुटने जवाब देने लगते हैं, चलना-फिरना, उठना-बैठना, यहां तक कि बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दोनों घुटनों का नी-रिप्लेसमेंट ऑपरेशन किया जाता है। इस सर्जरी में इसमें जांघ वाली हड्डी, जो घुटने के पास जुड़ती है और घुटने को जोड़ने वाली पैर वाली हड्डी, दोनों के कार्टिलेज काट कर उच्चस्तरीय तकनीक से प्लास्टिक फिट किया जाता है।

एनेस्थीसिया साइड इफेक्ट्स : कुछ बड़ी सर्जरी में बेसुध करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि रोगी को ऑपरेशन के दौरान दर्द का आहसास न हो। अधिकांश मामलों में एनेस्थीसिया सुरक्षित होता है और कोई समस्या पैदा नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इसके साइड इफेक्ट की गुंजाइश रहती ही है। इसके प्रतिकूल प्रभाव निम्न प्रकार से हो सकते हैं- ■ मतली और उल्टी, ■ चक्कर आना, ■ उनींदापन, ■ सांस की नली की सूजन, ■ दांतों को नुकसान, ■ वोकल कॉर्ड्स को चोट, ■ धमनियों में चोट

सर्जरी में डीप वेन थ्रंबोसिस का जोखिम: डीप वेन थ्रंबोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिस्म दोनों ही टर्म फेफड़ों में रक्त के थक्के जमने वाली स्थिति लिए प्रयोग की जाती हैं। सभी सर्जरी खून के थक्कों के बनने के जोखिम को बढ़ाती हैं, लेकिन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसी आर्थोपेडिक प्रक्रियाओं में जोखिम बढ़ जाता है। आमतौर पर सर्जरी के बाद के पहले दो हफ्तों के भीतर रक्त के थक्के ज्यादा जमते हैं। इसलिए इनके लक्षणों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि आपातकाल की स्थिति में समय से चिकित्सकीय मदद ली जा सके।

इंप्लांट विफल हो सकता है: कृत्रिम घुटने कई तरह से विफल हो सकते हैं, जैसे सर्जरी के बाद उनका न मुड़ पाना, दर्द बना रहना या ढीला हो जाना। घुटना ढ़ीला रह जाए तो इसे समायोजित करने की जरूरत पड़ती है।

ओस्टियोलिसिस हो सकता है: कुछ मरीजों में इंप्लांट वाले प्लास्टिक (पॉलीथीन) के टुकड़े शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने वाले कणों को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में वाइट ब्लड सेल इन कणों पर हमला कर उन्हें पचा सकती हैं। दुर्भाग्यवश वाइट ब्लड सेल हड्डियों को भी कमजोर बना सकती है।

क्या करें: जिन्दगी की भागदौड़ में घुटने अकसर कमजोर पड़ ही जाते हैं, इसलिए चलते-फिरते और यहां तक कि आराम के वक्त भी इनकी सेहत का ध्यान रखें। घुटनों ने यदि दर्द, सूजन या टेढ़ेपन जैसा कोई संकेत दिया है तो इसे नजरअंदाज न करें। दवाई, एक्सरसाइज और चिकित्सकीय मदद आदि विकल्प आपके घुटनों की उम्र बढ़ा सकते हैं।

शरीर के लिए विषतुल्य हानिप्रद गंदगी को शरीर से बाहर निकाल फेंकने के लिए उषा पान जैसा अमोघ अस्त्र भारतीय परंपरा की ही देन है, जो भारतीय महाऋषियों के शरीर विषयक सूक्ष्म एवं विषद अध्ययन की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। आइए जानें इसके लाभ।

बुढ़ापे से मुक्ति दिलाता है उषा पान...

काकचण्डीश्वर कल्पतन्त्र नामक आयुर्वेदीय ग्रन्थ में रात के पहले प्रहर में पानी पीना विषतुल्य बताया गया है। मध्य रात्रि में पिया गया पानी दूध के सामान लाभप्रद बताया गया हैं। प्रातःकाल यानी सूर्योदय से पहले पिया गया जल मां के दूध के समान लाभप्रद कहा गया है। यह इतना लाभप्रद है कि रोग और बुढ़ापे से मुक्ति दिला सकता है। लोहे के बर्तन में रखा हुआ दूध और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने वाले को कभी लिवर और रक्त संबंधी रोग नहीं होते और रक्त हमेशा शुद्ध बना रहता है। उषा पान के लिए पिया जाने वाला जल तांबे के बर्तन में रात भर रखा जाए, तो उससे और भी स्वस्थ्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे। जल से भरा तांबे का बर्तन सीधे भूमि के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, अपितु इसको लकड़ी के टुकड़े पर रखना चाहिए। और पानी हमेशा नीचे उकडू बैठकर यानी घुटनों के बल उत्कर आसान में बैठकर पीना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें यूरिक एसिड बढ़े होने की शिकायत है उनके लिए तो सुबह उषा पान करना किसी रामबाण औषिधि से कम नहीं है।

क्या है उषा पान

प्रातः काल यानी रात्रि के अंतिम प्रहार में पिया जाने वाल जल, दूध इत्यादि को आयुर्वेद और भारतीय धर्म शास्त्रों में उषा पान शब्द से संबोधित किया गया है। सुप्रसिद्ध आयुर्वेदीय ग्रन्थ 'योग रत्नाकर' सूर्य उदय होने के निकट समय में जो मनुष्य आठ प्रसर मात्रा में जल पीता हैं, वह रोग और बुढ़ापे से मुक्त होकर सौ वर्ष से भी अधिक जीवित रहता है।

कब करें उषा पान

प्रातःकाल बिस्तर से उठ कर बिना मुख प्रक्षालन यानी कुल्ला इत्यादि बिना किए हुए ही पानी पीना चाहिए। कुल्ला करने के बाद पिए जाने वाले पानी से सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। ध्यान रहे पानी मल मूत्र त्याग के भी पहले पीना है।

उषा पान के फायदे

सवेरे तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से अर्श यानी बवासीर, शोथ(सोजिश), ग्रहणी, ज्वर, पेट के रोग, बुढ़ापा, कोष्ठगत रोग, मोटापा, मूत्राघात, रक्त पित्त यानी शरीर के किसी भी मार्ग में होने वाला रक्त स्त्राव, त्वचा के रोग, कान नाक गले सिर एवं नेत्र रोग, कमर दर्द तथा अन्यान्य वायु, पित्त, रक्त और कफ, मासिक धर्म, कैंसर, आंखों की बीमारी, डायरियां, पेशाब संबंधी बीमारी, किड़नी, टीबी, गठिया, सिरदर्द आदि से संबंधित अनेक व्याधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं।

जल की नैसर्गिक शक्ति

जल में एक नैसर्गिक विद्युत होती है, जो रोगों का विनाश करने में समर्थ होती हैं। इसलिए जल के विविध प्रयोगों से शरीर के सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ज्ञान तंतुओ के चक्र पर अनूठा प्रभाव पड़ता है, जिस से शरीर के मूल भाग मस्तिष्क की शक्ति और क्रियाशीलता में चमत्कारिक बढ़ोतरी होती है। एक कहावत हैं-प्रातः काल खाट से उठकर, पिए तुरतहि पानी। उस घर वैद्य कबहुं नहीं आए बात घाघ ने जानी।

साफ जल के नुकसान

मगर आज एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जल को भी अति दूषित कर दिया गया है और इसको साफ करने के लिए जो विधियां हम इस्तेमाल करते हैं वे पानी को साफ तो करती हैं मगर साथ में पानी में मौजूद मिनरल्स भी निकाल देती हैं। इसलिए जब हम पहाड़ों पर कभी जाते हैं तो वहां के पानी में बहुत बढ़िया स्वाद आता है।

इम्पोरटेंट फेक्ट्स

दिल में आक्सीजन की कमी एन्जाइना का संकेत

कंठ-शूल (एन्जाइना) सीने में होने वाला दर्द या दबाव है जो हृदय में रक्त के प्रवाह में कमी के कारण उत्पन्न होता है। आपकी बांहों, जबड़े या पीठ के ऊपरी भाग में भी दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द इस बात का संकेत है कि आपके हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। यह इस बात का लक्षण है कि आपको दिल का दौरा रोकने के लिए उपचार की आवश्यकता है।

कंठ-शूल के लक्षण

एन्जाइना के लक्षण काफी कुछ दिल के दौरे के लक्षणों जैसे हो सकते हैं।

- सीने, बांहों, जबड़े, कंधों या गर्दन में दर्द या दबाव, या खिंचाव अथवा भारीपन महसूस होना।
- पसीना आना।
- सांस फूलना।
- मितली या उल्टी आना।
- पेट में दर्द।
- बेहद थकान लगना, चक्कर या बेहोशी महसूस करना।

कुछ लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते। अगर आप जो कुछ कर रहे हैं उसे रोककर आराम करें तो अक्सर एन्जाइना के दर्द में आराम मिल जाता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको एन्जाइना है, तो आपको दर्द होने पर दवा दी जा सकती है। इस दवा को नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं।

कब कराएं उपचार

एन्जाइना के लक्षण महसूस हो रहे हों और उसका उपचार करने के लिए दवा न हो। अपनी दवा ले ली हो लेकिन आपके लक्षण दूर न हो रहे हों या आपको ऐसे नए लक्षण महसूस हो रहे हों जो पहले कभी न हुए हों। आपातचिकित्सा टीम के आने तक बैठें या लेट जाएं। गाड़ी चलाकर अस्पताल न जाएं और न ही अपने डॉक्टर को फोन कर देर करें।

जरूरी सुझाव

आपको हृदय की समस्या है या नहीं यह देखने के लिए आपकी जांच की जाएगी। आपको दवाएं देनी शुरू की जा सकती हैं या आपके हृदय को रक्त प्रवाह में सुधार के लिए अन्य प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। आपके डॉक्टर आपको कम वसा वाला भोजन करने और अपने हृदय का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए व्यायाम करने का सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर नाइट्रोग्लिसरीन सुझाते हैं, तो अपने डॉक्टर के आदेश के अनुसार दवा का प्रयोग करें। अधिक जानकारी के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन हैंडआउट मांगें।

जान सकेंगे शादी के बाद की जिंदगी कैसे जीएं?

वैडिंग कोचिंग से हल होंगी परेशानियां

शादी का नाम सुनकर जहां दिल में गुदगुदी होती है, वहीं नए रिश्ते की शुरुआत के बारे में सोच कर मन आशंकाओं के समुद्र में गोते खाता रहता है। युवितयों के मन में अनेक सवाल जैसे शादी के बाद ससुराल में जींस पहनने देंगे या नहीं, पहली बार कौन सी डिश पकवाएंगे, पति को जाने मेरी किस बात का बुरा लग जाए, मायके ज्यादा आने देंगे कि नहीं, सासू मां का स्वभाव कैसा होगा, नौकरी करने देंगे या नहीं... आदि जहां परेशान करते हैं, वहीं निजी समस्याओं का भी डर सताता है, परंतु इन बातों का समाधान कहीं से नहीं मिलता। कौन समझे मन की बातें घर में दादी-नानी, मां, दीदी और भाभी की नसीहतें सुन-सुन कर दिल कई बार डरता है। सहेलियां हमउम्र होने के कारण उसकी परेशानियों को सुनकर भी कोई राय नहीं दे पातीं। ऐसे में आजकल वैडिंग कोचिंग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, कोचिंग में जाकर शादी से पहले हम खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं।

मिल जाते हैं सवालों के जवाब

विवाह से पहले ही रिश्तों और उनकी मर्यादाओं के साथ अन्य पहलुओं को भी समझ लिया जाए तो विवाह में बिखराव और अलगाव की नौबत नहीं आती। इसके लिए घर की किसी बुजुर्ग महिला की नसीहतों के अलावा दुल्हन के लिए वैडिंग कोचिंग बढ़िया रहती है, जहां उसे पति-पत्नी के संबंधों से ताल्लुक रखने वाले छोटे से छोटे सवालों के जवाब काउंसिलिंग में मिल जाते हैं। क्या है वैडिंग कोचिंग विदेशों की तर्ज पर अब महानगरों में भी वैडिंग स्ट्रेस कोचिंग सेंटर खुलने लगे हैं, जिससे विवाह के बाद ही नहीं, विवाह से पहले भी एक-दूसरे की पसंद-नापसंद, इच्छा-अनिच्छा आदि को समझने में आसानी हो। दोनों एक-दूसरे की जरूरतें समझने के साथ फैमिली प्लानिंग पर भी विचार कर सकें। सिर्फ 2-3 सिटिंग ही इसके लिए काफी हैं।

मानसिक तौर पर खुद को करें तैयार

मैरिज काउंसलर की मानें तो आज की पीढ़ी में पहले की तुलना में समर्पण, धैर्य और त्याग जैसी भावनाएं काफी कम होने लगी हैं, सो ऐसी कोचिंग उन्हें एक-दूसरे को समझने में मदद करती है। कामकाजी दुल्हनों को कई बार एकल परिवार के ही दायित्व निभाने में भी दिक्कत आती है। पति के साथ अहं का टकराव होने से भी वैवाहिक जीवन को संभाल पाना कठिन हो जाता है। सफल वैवाहिक रिश्ते के लिए युगल स्वयं को मानसिक स्तर पर पहले तैयार करें। विवाह से पहले घर बसाने के लिए व्यावहारिक बातों की शिक्षा परिवार के बुजुर्गों द्वारा जरूर दी जाती है, लेकिन उसमें भी अहम बातें छूट जाती हैं। प्री-मैरिटल काउंसिलिंग में विवाह योग्य लड़के-लड़कियों को एक-दूसरे के विचारों से सामंजस्य बैठाना सिखाया जाता है।

स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करती है, सुपारी

अक्सर देखा गया है कि सुपारी का इस्तेमाल ज्यादातर पूजा में किया जाता है। यह गर्ण तासीर की होती है। इसे जलाकर उसकी राख को दांतों को साफ किया जाता है और दांत चमकीले होते हैं। सुपारी बड़ी और छोटी होती है। आज हम आपको इसे इस्तेमाल करने पर होने वाले लाभ के बारे में बताएगें।

■ अगर आपके मसूड़ों से खून है तो सुपारी लेकर उसका मोटा कूटकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े से रोज कुल्ला करने पर मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है।

■ अगर आपको बहुत ज्यादा यूरिन की समस्या हो रहा है तो ऐसे में सुपारी का पाउडर लेकर 1 या 2 ग्राम गाय के घी के साथ इस्तेमाल करें।

■ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सुपारी में मौजूद टैनिन बहुत ही उपयोगी होती है।

■ इसका अधिक प्रयोग रक्तभार को कम करता है तथा चक्कर आने लगता है।

■ सुपारी का इस्तेमाल दांतों की सड़न को रोकने के लिए मंजन के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं।

■ अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो सुपारी को जलाकर उसका पाउडर बना लें और इससे रोजाना ब्रश करें।

■ अगर आपको कही चोट लगने से घाव हो गया हो और खून बह रहा है तो ऐसे में इसका बारीक पाउडर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है।

■ जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है और उसका मुंह सूखे तो वह एक सुपारी का टुकड़ा मुंह में रख लें। ऐसी करने से मुंह बार-बार नही सूखेगा।

■ दाद, खाज, खुजली और चकत्ते होने पर सुपारी को पानी के साथ घिसकर लेप करने से फायदा होता है। बहुत ज्यादा खुजली होने पर सुपारी की राख को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से लाभ होता है।

रेसिपी

फ्रूट क्रीम

सामग्री

400 ग्राम क्रीम, 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम सेब (कटा हुआ), 50 ग्राम अनार, 50 ग्राम पपीता(कटा हुआ), 50 ग्राम आडू (कटा हुआ), 50 ग्राम अनानास (कटा हुआ), 35 ग्राम बादाम (कटे हुए)

विधि

सबसे पहले एक बाऊल में क्रीम और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें सेब, अनार, पपीता, आडू, अनानास और बादाम डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज करें। फ्रीज करने के बाद पिस्ता और चेरी के साथ गार्निश करके सर्व करें।

रवा उत्तपम

सामग्री

1 कप रवा या सूजी, 1 छोटा चम्मच नमक, तीन चौथाई कप दही, आधा कप पानी, आधा छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट, 1 छोटा टमाटर, 1 छोटा प्याज, 1 छोटी शिमला मिर्च, 2 कटी हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, डेढ़ बड़े चम्मच तेल

विधि

बर्तन में सूजी, नमक और दही लें, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सभी सामग्रियों को आपस में मिला लें। मिश्रण को 10 मिनट के लिए अलग रखें। 10 मिनट बाद सूजी काफी पानी सोख लेगी, सूजी हल्की होनी चाहिए। उसमें चम्मच चलाएं, यदि जरूरत लगे तो थोड़ा पानी और मिलाएं। हरी मिर्च का डंठल हटा कर उसे अच्छे से धोकर काट लें। प्याज को धो लें और फिर इसे बारीक काट लें। टमाटर को भी छोटा-छोटा काट लें। शिमला मिर्च को बीच से दो भागों में काट लें तथा इसका डंठल और बीज हटा दें। अब शिमला मिर्च को धोकर छोटा-छोटा काट लें। सूजी के घोल में कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डाल कर अच्छे से मिलाएं। सूजी के मिश्रण में ईनो डालें और उसके ऊपर एक छोटा चम्मच पानी डाल कर घोल को अच्छे से एक दिशा में एक मिनट तक फेंटें। अब मध्यम आंच पर एक तवा गर्म करें और जब तवा गर्म हो जाए तो इसको गीले कपड़े या फिर किचन पेपर से पोंछ लें। एक चम्मच कटोरी में सूजी का घोल लेकर लगभग 4 इंच का उत्तपम फैलाएं। दोनों तरफ से थोड़ा तेल लगा कर इसे अच्छे से सेकें। इसमें 2-3 मिनट का समय लगता है। स्वादिष्ट और पौष्टिक उत्तपम तैयार है। सर्व करने के लिए, अब इसे सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

कर्नाटक सरकार के खिलाफ भाजपा के साथ आई जेडीएस

बेंगलूरू। कर्नाटक में कावेरी जल बंटवारा मुद्दा पर सियासत गरमा गया है। इसी बीच देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवगौड़ा ने जेडीएस के भाजपा में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के खिलाफ जहां बेंगलूरू में गांधी प्रतिमा के पास पूर्व मुख्यमंत्री धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एचडी कुमारस्वामी बंगलूरू में भाजपा के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्नाटक सरकार के खिलाफ कावेरी जल बंटवारा मुद्दा को लेकर भाजपा बेंगलूरू में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी भी शामिल हुए। उन्होंने भाजपा के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के बाद कहा, राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही। वह अब राज्य के किसानों के जीवन के साथ खेल रही है और इसी वजह से भाजपा और जेडीएस साथ में प्रदर्शन कर रही है।

लालू और नीतीश के बीच सीट बंटवारे पर नहीं बन पा रही बात

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) और लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बीच गहन बातचीत के बावजूद, आगामी 2024 लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर समझौता नहीं हो पाया है। सूत्रों ने इस बात का दावा किया है। यह विवाद मुख्य रूप से सीतामढी, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर और बांका में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन को लेकर है। रिपोर्टों से पता चलता है कि लालू यादव के नेतृत्व वाली राजद इन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारने पर अड़ी हुई है, सत्तारूढ़ जदयू ने इस प्रस्ताव को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। नीतीश खेमा उन सीटों को बरकरार रखने पर अड़ा है जहां जेडीयू मतदाताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। मौजूदा लोकसभा में जेडीयू के 16, बीजेपी के 17, एलजेपी के दोनों गुटों के छह और कांग्रेस के एक सदस्य हैं. निचले सदन में राजद की कोई मौजूदगी नहीं है।

सिविल कर्मचारी नहीं कर रहे आदेश का पालन : केजरीवाल

नईदिल्ली। आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर में सिविल सेवक सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और शीर्ष अदालत से दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र से चार सप्ताह में मामले का संकलन तैयार करने को कहा। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में असाधारण तत्परता है। सिविल सेवक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, अगले सप्ताह सात न्यायाधीशों की दो पीठें होंगी और उसके बाद कुछ संविधान पीठें होंगी। सिंघवी ने जवाब दिया, इस मामले को दूसरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इसे किसी न किसी तरह से सीधा करना होगा।

सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने पर कमलनाथ का तंज

भोपाल। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को सत्ताधारी भाजपा द्वारा राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में चार सांसदों और तीन केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा जितने सजावटी उम्मीदवार उतार रही है, जनता का गुस्सा उतना ही बढ़ रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जनता यह मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेगा उसका मंत्रालय, जो पहले से ही निष्क्रिय है, अब और भी निष्क्रिय हो जाएगा तो जनता के लंबित काम कैसे होंगे? इस कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। चुनाव लड़ने वाले सत्ताधारी सांसदों के संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा होगी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने आगे कहा, ये तथाकथित बड़े लोग पार्टी के दबाव में अनिच्छा से चुनाव लड़ेंगे और हारेंगे तो जनता के खिलाफ हो जायेंगे। जिससे जनता उपेक्षा और उत्पीड़न का शिकार होगी। इस कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है।

देश के संविधान को नहीं मानती भाजपा : महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का भाजपा आरोप लगाया। इसके साथ ही ताजा हमला करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाजपा देश के संविधान को नहीं मानती और इसे खत्म करने की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपने 'करीबी पूंजीपतियों' को फायदा पहुंचाने के लिए जम्मू-कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती मीडिया में आई उन खबरों को लेकर प्रतिक्रिया दे रही थीं जिनमें दावा किया गया है कि जम्मू क्षेत्र में पाए गए लिथियम के भंडार की जल्द ही नीलामी की जाएगी।

वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 साल पूरे होने पर मोदी ने कहा-

जल्द आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा भारत : प्रधानमंत्री

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में कहा कि उनका लक्ष्य भारत को वैश्विक विकास का इंजन बनाना है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश जल्द ही दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने 20 साल पहले वाइब्रेंट गुजरात के छोटे-छोटे बीज बोए थे और आज यह एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने राज्य को भारत का विकास इंजन बनाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया। 2014 के बाद हमारा लक्ष्य भारत को वैश्विक वृद्धि का इंजन बनाना है।

पीएम मोदी ने कहा कि देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि वह जल्द ही वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरी आपको गारंटी है कि अब से कुछ वर्षों में आपकी आंखों के सामने भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर डाला कि कैसे एक साधारण शुरुआत से वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम एक संस्थान में बदल गया है और बाद में कई राज्यों ने इसका अनुसरण करते हुए निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित किए।

वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी ने कहा कि यह समिट ऐसे समय में आयोजित की गयी थी जब तत्कालीन सरकार राज्य की औद्योगिक प्रगति को लेकर उदासीन थी। इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक कार्य तीन चरणों से होकर गुजरता है, पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, बाद में उसे विरोध का सामना करना पड़ता है और अंततः उसे स्वीकार कर लिया जाता है।पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमने न केवल गुजरात का पुनर्विकास किया बल्कि इसके भविष्य के बारे में भी सोचा, हमने इसके लिए वाइब्रेंट गुजरात को एक प्रमुख माध्यम बनाया। वाइब्रेंट गुजरात को गुजरात के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक

माध्यम बनाया गया और दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करने का एक माध्यम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने वर्षों में कई संकट झेले हैं। गुजरात में भूकंप और काल जैसा विकराल संकट झेला है। इसके अलावा आर्थिक संकट भी गुजरात झेल चुका है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेट सबमिट मेरे लिए मजबूत बॉन्डिंग का एक अहम प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उन्हें पता भी नहीं होगा कि पूर्व में गुजरात किस स्थिति को झेलता था। जब भूकंप आया तो हजारों लोगों की जान गई अकाल और भूकंप के अलावा एक बैंक भी था जो डूब गया जिससे गुजरात में आर्थिक हाहाकार मचा था। यह वह समय था जब मैं पहली बार विधायक बना मेरे लिए सब कुछ नया लेकिन चुनौती भी थी। इसी दौरान गोधरा की घटना भी हुई। यह सब देख कर मैंने प्रण लिया कि गुजरात को इस भयंकर स्थिति से बाहर निकाल कर रहूंगा। और एक आज का समय है जब दुनिया जीवन तो गुजरात वाइब्रेंट गुजरात की सफलता को शान से देख रही है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 'भविष्य का प्रवेश द्वार' विषय पर 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' का 10वां संस्करण अगले साल 10 से 12 जनवरी के बीच गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सचिव विनोद राव ने कहा कि बोदेली में एक सभा को संबोधित करने से पहले, प्रधानमंत्री राज्य सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' पहल के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे।

समिट में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना

पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करते हुए बताया कि उन्होंने एक बीज बोया था जो अब वटवृक्ष बन गया है। समिट में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात केवल ब्रांडिंग का कार्यक्रम नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा जुड़ाव का कार्यक्रम है। मेरे लिए यह वो जुड़ाव है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों और उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। 20 साल पहले हमने एक बीज बोया था, जो आज बड़ा एक विशाल और वृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन मुझे अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था।

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया था, जब तत्कालीन केंद्र सरकार गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ, इतना डराने के बाद भी विदेशी निवेशक गुजरात आए।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि साल 2009 में वैश्विक मंदी के दौरान भी इस समिट का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट गुजरात की सफलता में योजना, कल्पना और कार्यान्वयन शामिल है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। साल 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था।

मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर साधा निशाना

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया: खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मणिपुर की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया और मांग की कि वह अशांति को नियंत्रित करने के लिए पहले कदम के रूप में भाजपा के अक्षम मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया है और भाजपा पर मणिपुर को युद्ध के मैदान में बदलने का आरोप लगाया। 6 जुलाई से लापता दो छात्रों की हत्या का विरोध कर रहे आरएएफ कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच मंगलवार रात इंफाल के सिंगजामेई इलाके में झड़प हुई, जिसके बाद कानून लागू करने वालों को आंदोलनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और रबर की गोलियां चलानी पड़ीं।

खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा कि 147 दिनों से मणिपुर के लोग परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में छात्रों को निशाना बनाए जाने की भयावह तस्वीरों ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को हथियार बनाया गया था। खूबसूरत राज्य मणिपुर को भाजपा के कारण युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है! उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, पीएम मोदी भाजपा के अक्षम मणिपुर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। किसी भी आगे की उथल-पुथल को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम होगा। कांग्रेस मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रही है और सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री ने हिंसा प्रभावित राज्य का दौरा क्यों नहीं किया। पिछली रात छात्रों और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) कर्मियों के बीच झड़प के बाद बुधवार सुबह इंफाल में स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण रही। संभावित विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आशंका के कारण मणिपुर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

(सीआरपीएफ) और आरएएफ कर्मियों को इंफाल घाटी में बड़ी संख्या में तैनात देखा गया। हालाँकि राज्य सरकार ने बुधवार को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है, लेकिन इम्फाल स्थित कुछ संस्थानों के छात्रों ने अपने स्कूलों में इकट्ठा होने की कसम खाई है, जिससे दिन में और अधिक विरोध प्रदर्शन की अटकलें तेज हो गई हैं।

पूरे मामले की सीबीआई की टीम करेगी जांच : एन बीरेन सिंह

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि सीबीआई निदेशक एक विशेष टीम के साथ 6 जुलाई से लापता दो युवकों की हत्या की जांच करने जा रहे हैं। मंगलवार को दो लापता युवकों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य में छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल प्रतिबंध फिर से लागू हो गया। मंगलवार को इंफाल घाटी में कम से कम 45 छात्र घायल हो गए, जिनमें से कई लड़कियां थीं, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। यह बताते हुए कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार संपर्क में हैं, एक्स पर सीएम ने कहा, लापता छात्रों के दुखद निधन के संबंध में कल सामने आई दुखद खबर के आलोक में, मैं राज्य के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोनों राज्य और केंद्र सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए मिलकर काम कर रही हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

एशियन गेम्स में नेपाल क्रिकेट ने रचे नए इतिहास

हांगझोऊ। एशियन गेम्स में मेंस क्रिकेट में ग्रुप ए में नेपाल और मंगोलिया के बीच मैच खेला गया। इस टी20 इंटरनेशनल मैच में कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। नेपाल ने मैच में 273 रनों से जीत दर्ज की। मंगोलियाई गेंदबाजों को नेपाल के बल्लेबाजों ने खूब परेशान किया। कुशल मल्ला ने जहां टी20 इंटरनेशनल का सबसे तेज शतक ठोका तो वहीं दिपेंद्र सिंह ऐरी ने सबसे तेज फिफ्टी ठोक डाली।

वहीं कुशल मल्ला ने रोहित शर्मा, डेविड मिल और सुदेश विक्रमशेखर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो वहीं दिपेंद्र ने युवराज सिंह का 16 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला। दिपेंद्र टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज पचासा ठोकने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 10 गेंदों पर नॉटआउट 52 रन बनाकर लौटे दिपेंद्र ने महज 9 गेंदों पर ही पचासा ठोक दिया था। अपनी 10 गेंदों की पारी में दिपेंद्र ने आठ छक्के लगाए।

वहीं बता दें कि, टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम दर्ज था। जिन्होंने 2007 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में पचासा ठोका था। ये वही मैच था जब युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय में ऐसे ही सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड रोहित शर्मा, डेविड मिलर और विक्रमशेखर के नाम दर्ज था। इन तीनों ने 35-35 गेंदों पर शतक लगाया था।

वहीं नेपाल के कुशल मल्ला ने महज 34 गेंदों में सेंचुरी लगाई। इसके साथ ही कुशल ने इन तीनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 50 गेंदों में आठ चौके और 12 छक्कों की मदद से नॉटआउट 137 रन बनाए।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 66 हजार के पार बंद

नईदिल्ली। शेयर बाजार में बुधवार को तेजी दर्ज की गई और बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स शुरूआती गिरावट से उबरने के बाद 66 हजार के पार बंद हुआ। इससे पिछले दो कारोबारी सत्रों में बाजार में गिरावट देखी गई थी। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी के रुख के बीच सेंसेक्स में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस, एलएंडटी और आईटीसी जैसी कंपनियों के शेयरों में तेजी से बाजार को समर्थन मिला। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई । हालांकि, कारोबार के आखिरी एक घंटे में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला और सेंसेक्स 173.22 अंक या 0.26 प्रतिशत चढ़कर 66,118.69 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 65,549.96 अंक तक लुढ़क गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुआ।

अपोलो अस्पताल ने 102 करोड़ रुपये में किया मेडिकल फैसिलिटी का अधिग्रहण

नईदिल्ली। अपोलो अस्पताल ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 325 बिस्तर के आंशिक रूप से निर्मित अस्पताल का अधिग्रहण किया है। अपोलो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड ने फ्यूचर ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का 102 करोड़ रुपये के नकद सौदे में अधिग्रहण किया। अपोलो मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनलिस्टेड सब्सिडियरी कंपनी है। अपोलो अस्पताल की प्रबंध निदेशक (स्ब) सुनीता रेड्डी ने कहा कि यह देशभर में योजनाबद्ध क्षमता विस्तार का हिस्सा है और इससे क्षेत्र में और भी अधिक लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा।

एएमएनएसइंडिया का हजीरा प्रोजेक्ट 2026 तक होगा चालू

नईदिल्ली। आर्सेलरमित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल ने बुधवार को भरोसा जताया कि एएमएनएस इंडिया की हजीरा परियोजना 2026 तक चालू हो जाएगी। फिलहाल परियोजना विस्तार के चरण में है। आर्सेलर मित्तल की इकाई एएमएनएस इंडिया ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि वह हजीरा में इस्पात संयंत्र क्षमता बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन करने के लिये 60,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। मित्तल ने 'वाइब्रेंट गुजरात' शिखर सम्मेलन के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यहां कहा, ''हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र और गुजरात सरकार के सहयोग से हम 2026 तक इस परियोजना को चालू करने में सक्षम होंगे।'' उन्होंने कहा कि हजीरा विस्तार परियोजना तेज गति से आगे बढ़ रही है और इसके निर्माण में 20,000 से अधिक लोग शामिल हैं। मित्तल ने कहा, ''हमारा पहले चरण में अपनी उत्पादन क्षमता को दोगुना और फिर इसे तीन गुना करने का लक्ष्य है।

अगस्त में 2.67 प्रतिशत बढ़ा क्रेडिट कार्ड से खर्च

नईदिल्ली। भारत में लगातार लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। प्वाइंट ऑफ सेल और ई-कॉमर्स पेमेंट्स में दमदार बढ़ोतरी के चलते भारतीयों के बीच क्रेडिट कार्ड से खर्च जुलाई 2023 में 1.45 लाख करोड़ रुपये था जो अगस्त में 2.67 प्रतिशत बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपये की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। प्वाइंट ऑफ सेल, जिसके माध्यम से कस्टमर पेमेंट करता है, पर ट्रॉन्जैक्शन्स लगभग 6.7 प्रतिशत बढ़कर 52,961 करोड़ रुपये हो गया जबकि ई-कॉमर्स पेमेंट्स बढ़कर 95,641 करोड़ हो गया। बैंकों में, क्रेडिट कार्ड प्रमुख एचडीएफसी बैंक का ट्रॉन्जैक्शन पिछले महीने के 39,403 करोड़ से 0.1 प्रतिशत घटकर अगस्त में 39,371 करोड़ हो गया। आईसीआईसीआई बैंक ने ट्रॉन्जैक्शन में लगभग 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 26,606 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की।

घरेलू बचत को लगी बड़ी चपत

अनिल तिवारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में लोगों की शुद्ध घरेलू बचत 55त्न गिरकर जीडीपी के 5.1 प्रतिशत पर आ गई, जबकि इन परिवारों पर कर्ज का बोझ दोगुना से भी अधिक होकर 15.6 लाख करोड रुपए पहुंच गया। देश में घरेलू बचत पिछले 50 साल में सबसे कम होने और कर्ज का बोझ बेतहाशा बढ़ने का मुद्दा गरमाने के बाद वित्त मंत्रालय ने एक्स पर लिखा है कि लोगों में कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, ज्यादातर लोग घर और गाड़ियां, गहने, सहित अन्य विलासी उपभोक्ता सामान कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, इससे घरेलू बचत कम हुई है। इसलिए वित्तीय संकट जैसी कोई बात नहीं है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी घरेलू बचत, प्रति व्यक्ति आय और क्रय शक्ति की मौजूदा स्थिति के मानदंड पर परखी जाती है। नोटबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब गंभीरता से दर्ज किया गया कि भारत में घरेलू बचत लगातार गिरावट की ओर है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह पिछले 5 दशक में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय स्टेट बैंक की आख्या के मुताबिक परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत में करीब 55 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के पास पहुंचती है।

मालूम हो कि वित्त वर्ष 2020-21 में यह जीडीपी के 11.5त्न पर थी जबकि महामारी से पहले वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 7.6 प्रतिशत पर था। हालांकि वित्त मंत्रालय ने घरेलू बचत में गिरावट पर सफाई देते हुए कहा है कि लोग अब आवास और वाहन जैसी भौतिक संपत्तियों में अधिक निवेश कर रहे हैं जिसका सीधा असर घरेलू बचत पर

पड़ रहा है।

वित्त मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया है कि संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है। सरकार ने तर्क दिया है कि पिछले 2 सालों में लोगों ने खुदरा ऋण का 55त्न आवास, शिक्षा और वाहन पर खर्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तथ्य बाहर आने के बाद से ही राजनीतिक दल तथा सोशल मीडिया में इसे लेकर विमर्श तेज हो गया है। बचत को लगी बड़ी चपत के मीम्स भी ट्रेंड हो रहे हैं।

विशुद्ध भारतीय जनमानस सनातन से बचत की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता रहा है। शायद इसी कारण अपेक्षाकृत कम में जीवन यापन कर लेने के सिद्धांत के उलट बात करने वाले चार्वाक, ओशो सरीखे लोगों को भी कभी गंभीरता से नहीं सुना गया। ऋषि चार्वाक ने कहा था यावज्जीवेत्सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। यानी मनुष्य जब तक रहे सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी पिए। भारतीय समाज में इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया और आज भी गाहे बगाहे इसका उपयोग व्यंग्य के तौर पर ही किया जाता है।

वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए अनेक ढांचागत और मौद्रिक सुधार किये ताकि संरचनात्मक सुधार के साथ ही पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के क्षेत्र में सुधार किया जा सके। अनेक क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु आए दिन नई-नई नीतियों के आगमन से घरेलू बचत लगातार प्रभावित हुई। नोटबंदी, नियंत्रण मुक्त ईंधन की कीमत, आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे कार्यक्रमों का असर घरेलू बचत पर पड़ा। इतिहास साक्षी है कि जब दुनिया वर्ष 2008 की महामंदी में झूल रही थी तब भारत ने अपनी घरेलू बचत के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था का दम बनाए रखा था। नोटबंदी के कारण महिलाओं द्वारा की जाने वाली बचत भी फुस्स हो गई ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गए शोध की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बचत से निकासी का एक बड़ा हिस्सा भौतिक संपत्तियों में चला गया है और 2022-23 में इन पर कर्ज भी 8.2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। करोना महामारी के दौरान घरेलू ऋण एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बढ़ा था लेकिन अब उसमें भी गिरावट आई है। मार्च 2020 में यह अनुपात 40.7त्न था लेकिन जून 2023 में यह घटकर 36.5 प्रतिशत पर आ गया है।

ठगेश सरकार को हटाना है, प्रदेश में भाजपा का परचम लहराना है : बृजमोहन

रायपुर। भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल की उपस्थिति में पूर्व मंत्री व रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 1500 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पिछले विधानसभा चुनाव में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बूथ, वार्ड, मंडल के कार्यकर्ताओ को मंच पर बुलाकर सम्मान किया गया।कार्यक्रम में पहुंची महिला कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर अच्छा खासा जोश दिखा। कार्यकर्ता सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी ने कहा कि आज से चुनाव शुरू हो गए हैं आप सभी कार्यकर्ताओं को योजना बनाकर अपना काम शुरू कर देना चाहिए और मैं यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आज आप यह संकल्प लेकर जाएं कि मैं अपना बूथ जिताऊंगा। आपने लगातार सात बार से विधानसभा को जिताया है कुछ एंटी इनकंबेकी होती है।

सड़कों में डबरा है इस डबरे में लबरे को डुबोना है

रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि आगामी माह में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है आज जो हम यहां एकत्रित हुए हैं हमको पूरे तन ,मन ,धन से शंखनाद करते हुए बिगुल फूंक देना चाहिए और दक्षिण विधानसभा के साथ-साथ पूरे प्रदेश में कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा आज सड़कों में डबरा है इस डबरे में लबरे को डुबोना है । मैं धमतरी गया था तो वह सड़कों पर डबरे को देखकर निषाद समाज के लोगों ने मुझे कहा कि इसका पट्टा दिला दो हम इसमें मछली पालन करेगें। 15 साल तक रायपुर को विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था परंतु पिछले 5 वर्षों में एक भी विकास के कार्य कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है पूरे शहर को खोद दिया गया है हमारे समय में बस स्टैंड बना, एक रुपए किलो में चावल मिला , बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी खुली अब तो विकास कार्य रुक से गए हैं शारदा चौक चौड़ीकरण के लिए आज निकले हैं जबकि उसका टेंडर भी नहीं हुआ है बजट की भी व्यवस्था नहीं है मुआवजा भी नहीं मिला है 550 करोड़ की लागत से तेलीबांधा से जोरा तक ओवर ब्रिज बनाने कांग्रेस सरकार बोल रही हैं वह क्या 1 दिन में बन जाएगा।

हमारी बहनें अब पंचायत के साथ-साथ विधानसभा और लोकसभा में भी नेतृत्व करेंगी : सुनील सोनी

रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आज इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में हमारी बहनें, माताएं आई हैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सभी से जो वादा किया था उसे पूरा किया 20 तारीख को महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। यहां के 9 सांसदों ने वोट डाला और 21 तारीख को 33त्न महिला आरक्षण का बिल पास हो गया इसके लिए आप सभी को मोदी जी को बधाई देनी चाहिए ।हमारी बहनें अब पंचायत के साथ-साथ विधानसभा और लोकसभा में भी नेतृत्व करेंगी । कांग्रेस ने इस बिल को अटकने का काम किया। परंतु मोदी जी ने ठान लिया था और इस बिल को लाकर पास करवा दिया ।यह महिलाओं के प्रति उनकी प्रगतिशील सोच को दर्शाता है।

दक्षिण के रास्ते ही पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभावित करना है : अजय

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय चंद्राकर जी ने कहा कि दक्षिण विधानसभा जब से बनी है तब से हम जीत रहे हैं परंतु चारों सीटों पर एक साथ सफलता नहीं मिल पाई है आज जो आप लोग योजना बनाकर धरना प्रदर्शन करते हैं यह इससे शहर प्रभावित होता ही है प्रदेश को भी प्रभावित करना है और इसकी शुरुआत आज दक्षिण विधानसभा से करनी होगी आप अपना ऐसा कार्य करें ऐसे मुद्दे उठाएं ऐसा प्रदर्शन करें कि पूरे के पूरे 90 विधानसभा प्रभावित हो सके दक्षिण के रास्ते ही पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभावित करना है । आज राजधानी की पहचान लूट हत्या डकैती के रूप में हो रही है आप सबको पिछली बार से ज्यादा लीड से दक्षिण में विजय दिलानी है । आज हम यहां से संकल्प ले तो छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भूगोल ,इतिहास बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण माननीय अटल जी ने किया था छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है ।

द .विधान सभा के लोगों का लगातार मिल रहा पुरजोर समर्थन : प्रेमप्रकाश पाण्डे

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वा लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी को लगातार 7 बार द , विधानसभा का आशीर्वाद मिलता है। इस लिए मुझे यकीन है कि आगे भी उन्हें ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहा है। परंतु ये भी समझना भी जरूरी है कि कहीं कोई चूक न हो जाए , इस लिया हमेशा तैयारी करते रहना चाहिए। अग्रवाल जी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य की नीव मध्य प्रदेश विधान सभा में रहते हुए किया था। इस सरकार ने प्रदेश के किसान, व्यापारी, युवाओं को धोखा दिया है। ऐसी लुटेरी सरकार को बदलना पड़ेगा। चुनाव शुरू हो चुके हैं, हमें अपने बूथ को जीतने का संकल्प करना है। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने माना कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अंधेरे की ओर धकेल दिया है। अबकी बार महिलाओं, किसानों, युवाओं के साथ किए गए धोखे का बदला लेने बारी है। सभी कार्यकर्ता बंधु से, खासकर बहनों से कि अपने घर व आस पड़ोस में सभी को जागरूक करें। भूपेश सरकार से मेरा कहना है की अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाने वाली है। कार्यक्रम में विजय केसरवानी, जयंती पटेल, सुभाष तिवारी,मोहन एंटी, मीनल चौबे, रमेश ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पार्षद, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा साहू, जिला अध्यक्ष सुभाष तिवारी, , गोविंद गुप्ता, प्रेमप्रकाश जी, रामकृष्ण, युवा मोर्चा अध्यक्ष , महिला मोर्चा अध्यक्ष समेत कई शीर्ष नेता एवं सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे ।

भूपेश के एटीएम के वजन से दबा है गांधी परिवार: ओपी चौधरी

रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छत्तीसगढ़ में माफिया सरकार चल रही है। सब जगह माफिया राज कांग्रेस ने स्थापित किया है। इस माफिया राज की कड़ी में पीएससी है और जो अन्य भर्ती एजेंसी हैं, वहां पर भी कांग्रेस ने माफिया राज्य स्थापित किया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अभी राहुल गांधी आए थे। बिलासपुर में युवा जगह जगह आक्रोशित होकर खड़े थे। भूपेश बघेल ने पुलिस पर दबाव डालकर उन लोगों को रुकवाया। जब रेल में राजनीतिक नौटंकी करने के लिए राहुल गांधी जाने लगे तो वहां पर युवाओं ने पीएससी पर सीधा सवाल किया। सीधी शिकायत की। पीएससी धांधली पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या? राहुल गांधी के सामने युवाओं ने शिकायत कर दी और बताया कि प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री निवास में लिखित में शिकायत की है लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा। दरअसल भूपेश बघेल के एटीएम तले राहुल दबे हुए हैं। इसीलिए

युवाओं के मसले पर कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सकते क्योंकि गांधी परिवार का एटीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बना रखा है और भूपेश का जो एटीएम है उसके वजन के तले राहुल गांधी दबे हुए हैं। इसलिए युवा भाई बहनों के अधिकार, उनके हक की बात पर राहुल कुछ नहीं बोल रहे। यदि राहुल में जरा भी नैतिकता रहती तो रेल के सफर में ही कार्रवाई हो जाती। चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने 18 लोगों की नियुक्ति पर स्थगन दिया है। इस तरह की स्थिति जब सामने हैं तो भूपेश बघेल कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहन देख रहे हैं। सबके सामने है कि किस तरह का आक्रोश छत्तीसगढ़िया युवा के मन में है। किस तरह की हताशा, किस तरह की निराशा है। कैसे वे युवा जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं।

बदलेगी तस्वीर स्टेशन रायपुर की, 463 करोड़ की लागत से होगा पुनर्विकास

रायपुर। रेल मंत्रालय के महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। अगस्त 2023 में माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा देश के 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ रायपुर स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। लगभग 70 एकड़ में विस्तृत रायपुर स्टेशन को आने वाले 45 सालों के यात्रियों की संख्या को ध्यान में रख कर इस वृहत कार्य की योजना बनाई गई है।

रायपुर रेलवे स्टेशन को विकसित करने का लक्ष्य रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना है। रेलवे स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे देश की लाइफलाइन है। रेलवे लगातार यात्री सेवा को सुलभ करने के लिए नवीनतम तकनीक, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में देशभर के रेलवे स्टेशनों की कायापलट करने पर काम किया जा रहा है शहरों की पहचान भी रेलवे स्टेशनों से जुड़ी होती है। रायपुर शहर की इतिहास में रायपुर रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए।

लोरमी पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा

कांग्रेस सरकार ने जनता को किया गुमराह: मीनाक्षी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे लेकर भाजपा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बस्तर संभाग से की है, जो इन दिनों मैदानी इलाके तक पहुंच गई है. इसी बीच मुंगेली जिले के लोरमी पहुंची परिवर्तन यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों ने नगर में जगह-जगह भव्य स्वागत किया.

हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सहित पदाधिकारी मानस मंच में आयोजित सभा में शामिल हुए. वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने लोरमी विधानसभा क्षेत्र पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को कांग्रेस सरकार ने गुमराह करने का काम किया.

नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल ने सभा को संबोधित कर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का आगाज हुआ है. छत्तीसगढ़ में इस परिवर्तन यात्रा के तहत हम जागरण करने निकले हैं. इस बार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की विदाई तय है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी. यह हम इस परिवर्तन यात्रा के दौरान गांव शहर कस्बा मोहल्ले में देख रहे हैं, जहां यात्रा को अच्छा प्रतिसाद आशीर्वाद जनता का प्राप्त हो रहा है . उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में इस बार परिवर्तन की लहर है.

चंदेल ने इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 75 पार के सवाल पर कहा, भाजपा ने पहले ही 21 विधानसभा के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है. जल्द ही दूसरी सूची भी जारी हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो पहले एक सूची तो जारी करे. उन्होंने कहा हम 6 सितंबर को जारी करेंगे, हमारा 17 अगस्त को हो गया. एक महीने पूरे हो गए, जो दंगल फिल्म चल रहा है न गदर, वही गदर कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा.

भारत के पर्यटन मानचित्र पर दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सरोदा दादर गांव

रायपुर। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के सरोधा-दादर गाँव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। सरोधा दादर को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया। पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित समारोह में सरोधादादर गाँव के मंगल सिंह धुर्वे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने भारत के पर्यटन मानचित्र पर कबीरधाम जिले के ग्राम सरोदा दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा नहीं चाहती 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हो

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी हो इसीलिये मोदी सरकार ने 86 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को घटाकर 61 लाख कर दिया है। मोदी सरकार धान की कीमत समर्थन मूल्य से ज्यादा देने पर

भी अडंगा लगाती है। मोदी सरकार के प्रतिबंध के कारण ही भूपेश सरकार को किसानों को 2500 कीमत देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू कर 9000 रू. प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देना शुरू किया था ताकि किसानों से किया वादा कांग्रेस सरकार पूरा कर सके। भाजपा को वोट देने का मतलब है धान खरीदी बंद करना और आने वाले समय में धान की पूरी कीमत नहीं मिलना होगा। भाजपा की मोदी सरकार धान पर घोषित समर्थन मूल्य से 1 रू. भी ज्यादा देने के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भले ही मोदी सरकार एक भी दाना चावल मत लें कांग्रेस सरकार किसानों से पूरा धान खरीदेगी। कांग्रेस सरकार राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी तथा इस साल 125 लाख मीट्रिक धान की रिकार्ड खरीदी की जायेगी। भूपेश है तो भरोसा है कि आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ का किसान 3600 रू. प्रति क्विंटल में धान की कीमत पायेगा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ का किसान पूरे देश में धान की सबसे ज्यादा कीमत 2640 रू. पाया है।

मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के खिलाफ भाजपा के नेता झूठ फैला रहे हैं : ठाकुर

रायपुर। भाजपा सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, अशोक बजाज के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर दिए बयान को हास्यास्पद बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा

कि मुख्यमंत्री आवास योजना प्रदेश के उन लोगों को लाभ पहुंचा रही है जिन्हें मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूर रखा है। जिनका मुख्यमंत्री आवास योजना की सर्वेक्षण सूची में नाम आया है। गरीबों के आवास के विरोधी भाजपा नेता अब मुख्यमंत्री आवास योजना को लेकर झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। पहले मोदी सरकार ने प्रदेश के लाखों गरीबों को उनके आवास के अधिकार से वंचित रखा और अब मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना से उन गरीबों के सिर पर छत आ रहा है स्वयं का घर का सपना पूरा हो रहा है तब भाजपा के नेता अफवाह फैला रहे है। कांग्रेस से जुड़े लोगो को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं को बताना चाहिए क्या प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही भाजपा से जुड़े लोग नहीं है? भूपेश सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, बिजली बिल हाफ योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, स्वास्थ्य योजना खाद्यान्न योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना सहित सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ रमन सिंह, धरमलाल कौशिक सहित भाजपा से जुड़े अनेक नेता कार्यकर्ताओं उठा रहे हैं।

कांग्रेस का विरोध करते-करते जनता की विरोध कर रहे: शुक्ला

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय से भाजपा डर गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो गयी है। वह भूपेश सरकार के द्वारा लिये जा रहे जनकल्याणकारी

निर्णयों से घबरा गयी है। भाजपा आने वाले चुनाव में झूठ और भ्रम के सहारे राजनीति करना चाह रही। भाजपा युवाओं के बेरोजगारी भत्ते का भी विरोध करने लगी है। लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता लोकप्रिय योजनाओं के बारे में झूठे और अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। उन्हें लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में उनका वजूद खतरे में पड़ गया है इसीलिये वे कांग्रेस सरकार का विरोध करते-करते बौखलाहट में जनता से जुड़ी योजनाओं का विरोध करने लगे है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के युवा भूलें नहीं है कैसे भाजपा के 15 साल के राज में युवाओं का शोषण हुआ था, सरकारी विभागों में भर्तियां बंद कर दी गयी थी, छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने के बजाय संविदा और आऊट सोर्सिंग के माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियों पर रखा जाता था। भाजपा ने 2003 में युवाओं से वायदा किया था कि उनकी सरकार आने पर 500 रू. बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन तीन बार सरकार में आने के बाद भी भत्ता नहीं दिया।

मोदी सरकार के ओबीसी विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन आज

रायपुर । जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने कहा है की देश की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी को आखिर इतनी नफरत क्यों है? स्वयं पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का ढोंग करने वाले मोदी जी जब-जब पिछड़ा वर्ग को कुछ देने की बारी आती है तब-तब हमेशा ही अन्य पिछड़ा वर्ग को निराशा किया है। देश भर के लगभग सभी ओबीसी वर्ग के नेता जातिगत जनगणना कराये जाने के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से लगातार अनुरोध किया कि जनगणना रजिस्टर में जाति का कालम जोड़ा जाए लेकिन अपने आप को पिछड़ा वर्ग का हितैषी प्रचारित करने वाले मोदी सरकार, आरएसएस और भाजपाई नहीं चाहते की ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में न्याय मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा और केन्द्र की मोदी सरकार नही चाहती कि पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, समाजिक स्थिति का सही आंकलन होचन्द्राकर ने कहा है कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कि आरक्षण विरोधी सरकार में पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के मुद्दे पर ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र में यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना ैम्ब्ब् शुरु करवाया। मनमोहन सरकार के द्वारा 2013 में आर्थिक जाति जनगणना पूरी हुई, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इन जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया।

प्रदेश सरकार की बदनीयती का परिचायक : साहू

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू व अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली ही सूची में कांग्रेस नेताओं और उनके परिजनों का नाम होने के खुलासे के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बदनीयती पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर जो झूठ का नया जाल बुना है, उसका सच सामने आने लगा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा शुरू से ही प्रदेश को कांग्रेस और प्रदेश की झूठ शिरोमणि भूपेश सरकार की इस योजना को एक नए घोटाले की शुरुआत बता रही है और रायपुर जिले के कोपरा में योजना की शुरुआत से ही जन आक्रोश सामने आया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि ग्राम पंचायत कोपरा में मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की 44 नामों की जो सूची आई है, उसमें अधिकतर बड़े परिवारों वालों के नाम दर्ज हैं। इनमें जिला महामंत्री, जोन कांग्रेस के अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस सदस्य, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों के सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पत्नी, भाइयों के नाम गरीबों की इस तथाकथित आवास योजना की सूची में हैं। इनके पास पक्के मकान व खेती भी हैं। एक कांग्रेस नेता के तो तीन भाइयों के नाम इस आवास सूची में हैं। इसे लेकर विशेष ग्राम सभा में ग्रामीणों ने खुलकर एक साथ विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग रोजी मजदूरी करके घर चलाते हैं। हमारे पास कच्चा मकान है।

छत्तीसगढ़वासियों को ठहरने की मिलेगी बेहतरीन सहूलियत : सीएम बघेल

- 60 करोड़ 40 लाख की लागत से तैयार हुआ है सर्वसुविधायुक्त छत्तीसगढ़ निवास

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल शुभारंभ कर छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नई दिल्ली में ठहरने के लिए छत्तीसगढ निवास के रूप में नया भवन मिल गया है। इससे प्रदेश के जरूरतमंदों को सहित सभी के रूकने-ठहरने की दिक्कत दूर हो जाएगी।

गौरतलब है कि नई दिल्ली द्वारका के

सेक्टर 13 में बने इस नए छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपये है। भवन में 61 कमरे, 13 सूट है जो की आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है।पिछले तीन सालों में विभिन्न बाधाओं (जिसमें कोरोना काल) को पार कर छत्तीसगढ़ के निवासियों की सेवा के लिये देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास

तैयार किया गया है। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु इसकी परिकल्पना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की थी। हालांकि, पहले से छत्तीसगढ़ शासन के दो भवन छत्तीसगढ़ भवन चाणक्यपुरी व छत्तीसगढ़ सदन सफ़दरजंग हॉस्पिटल के पास नई दिल्ली में अवस्थित है। परंतु आधुनिक एवं छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए तीसरे भवन की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही थी।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने तीन वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास किया था। इसके लिए नई दिल्ली के द्वारका में नये छत्तीसगढ़ निवास के निर्माण की परिकल्पना की गई और इसकी आधारशिला 19 जून 2020 को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल शिलान्यास कर रखी थी। यह पहला मौका है कि जब पहली बार इस प्रकार की महत्वपूर्ण अत्याधुनिक भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से बाहर सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक मील का पत्थर है।

बस्तर संभाग के 56 गांव जो पूर्व में अंधेरे में डूब गए थे, उन्हें फिर रोशन करने में मिली सफलता

रायपुर। बस्तर संभाग के अतिसंवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रों में 56 गांवों को फिर बिजली से रोशन करने में सफलता पा ली गई है, जिनमें पूर्व में पहुंचाई गई विद्युत व्यवस्था को ध्वस्त कर, फिर से अंधेरे में डूबो दिया था। अब इन गांवों में निरंतर, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। पहले इन गांवों में सौर ऊर्जा और ग्रिड लाइन से बिजली पहुंचाई गई थी, लेकिन यहां के विद्युत लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जहां सोलर पैनल थे, उन्हें भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था या उखाड़ दिया गया था। जिसके बाद से इन गांवों में बिजली

पहुंचाना कठिन चुनौती बनी हुई थी। इन गांवों में पुनः विद्युत आपूर्ति बहाल हो सके, इसके लिए विशेष प्रयास कर इन अतिसंवेदनशील 56 गांवों में एक बार फिर से बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया गया है।

बस्तर संभाग के ये गांव वनाच्छादित, दूरस्थ-दुर्गम और अतिसंवेदनशील हैं। इन ग्रामों में बिजली लाइन बिछाना अत्यंत दुष्कर कार्य था, मुख्यालय से चिन्हांकित स्थल तक विद्युत सामग्री पहुंचाना पहली चुनौती थी, क्योंकि ये गांव घने जंगल में हैं और कहीं कहीं आवागमन भी कठिन था, साथ ही अतिसंवेदनशील क्षेत्र में स्थित हैं। इन गांवों में ग्रिड से सीधे बिजली पहुंचने से 6436 परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।

विगत 05 वर्षों में दंतेवाड़ा जिले के ऐसे 24 गांव, (लाभान्वित परिवार-3,798) सुकमा के 07 गांव , बीजापुर के 18 ग्राम (लाभान्वित परिवार-1,821) एवं नारायणपुर के 7 ग्राम (लाभान्वित परिवार -134) में फिर से बिजली पहुंचाई गई है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.